

## भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह\*

2010-11 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में सुधार होने पर भी भारत को एफडीआई का प्रवाह मंद बना रहा जबकि वैश्विक सुधार के पहले देशी आर्थिक निष्पादन सुदृढ़ था। पेपर में पैनल-कार्य के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2010-11 के दौरान भारत को वास्तविक एफडीआई का प्रवाह उसके संभाव्य स्तर से कम रहा (जो कि निहित समष्टिआर्थिक मानदंड दर्शाता है) जिसका आंशिक कारण कॉफमॅन्स इंडेक्स से की गई माप के अनुसार नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि होना था।

2010-11 में भारत को एफडीआई का प्रवाह कम रहा जबकि एशिया और लैटिन अमरीका में अन्य बाजार अर्थव्यवस्थाओं में काफी अंतर्वाह प्राप्त हुए। इससे अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान भारत में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3.0 प्रतिशत के वहनीय माने गए स्तर से बढ़ जाने से चिंता उत्पन्न हो गयी थी। यह बात इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाती है कि एफडीआई को सामान्यतः पूंजी प्रवाह का सर्वाधिक स्थिर घटक माना जाता है जो कि चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा, यह निवेश योग्य संसाधन बढ़ाता है, उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाता है, उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है और निर्यातों को बढ़ावा देता है।

अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की एफडीआई नीति के अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभ में भारत का दृष्टिकोण परंपरात्मक रहा है किंतु 1990 की प्रारंभिक अवधि से इसने अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधिक उदारकृत नीतिगत रुझान, विशेष रूप से अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तक अधिक पहुंच, कारोबार प्रारंभ करने में सहजता, लाभांश और लाभ का प्रत्यावर्तन और इक्विटी प्राप्ति के मानदंडों में शिथिलता के अनुरूप धीरे-धीरे स्थिति में सुधार किया। इस बढ़ते हुए उदारकरण के साथ-साथ समष्टिआर्थिक मूल तत्वों में पर्याप्त सुधार के परिणामस्वरूप वर्तमान सहस्राब्दि के पहले दशक में देश में एफडीआई का प्रवाह लगभग 5 गुना बढ़ गया।

उदार नीतिगत रुझान और मजबूत आर्थिक मूल तत्वों के चलते पिछले एक दशक में भारत में एफडीआई का प्रवाह तेजी से

\* यह एक अनुसंधान अध्ययन है जिसे आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक में तैयार किया गया है।

बढ़ने और उसका आवेग वैश्विक वित्तीय संकट (2008-09 और 2009-10) के दौरान बने रहने के बावजूद, निवेश प्रवाह में बाद में नरमी आना और वह भी तेज सुधार होने पर भी, कुछ अजीब बात है। पेपर में प्रस्तुत विश्लेषण और प्रायोगिक साहित्य का सर्वेक्षण दर्शाता है कि एफडीआई प्रवाह में यह अंतर कुछ संस्थागत कारकों का परिणाम हो सकता है जिन्होंने आर्थिक मूल तत्वों में निरंतर मजबूती रहने के बावजूद निवेशकों के उत्साह को कम किया। पैनल एक्सपर्ट्स, जिसमें पिछले 7 वर्षों में 10 चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मूलतत्वों की एफडीआई की प्रवृत्ति की जांच की गई, के निष्कर्षों से पता चलता है कि समष्टि मूलतत्वों के अलावा, क्रियाविधिक अपेक्षाएं पूरी करने में लगे समय जैसे संस्थागत कारक, एफडीआई अंतर्वाहों को काफी प्रभावित करते हैं।

इस पेपर की संरचना निम्नवत है: भाग 1 में वैश्विक निवेश प्रवाहों की प्रवृत्ति दी गई है जिसमें उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और भारत पर विशेष फोकस रखा गया है। भाग 2 में भारत की एफडीआई नीति की संरचना का विकास दर्शाया गया है जिसके बाद देश-वार अनुभव दिए गए हैं जो चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की नीति को दर्शाते हैं। भाग 3 में भारत में 2010-11 में एफडीआई प्रवाहों में तुलनात्मक कमी आने के कारणों की चर्चा की गई है और पैनल अनुमान का उपयोग करके इकोनोमेट्रिक तथ्य पर पहुंचा गया है। अंतिम भाग में निष्कर्ष दिए गए हैं।

### भाग 1: अंतर्वाहों की प्रवृत्तियां

अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में अंतर बढ़ने जाने और उभरते विश्व में पूंजी खाता क्रमिक रूप से खुलने से पिछले दो दशकों में सीमापारीय निवेश प्रवाहों में तेज वृद्धि हुई है। इस भाग में वैश्विक पूंजी प्रवाहों और विशेष रूप से भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाहों की हाल की प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

#### 1.1 एफडीआई अंतर्वाहों की वैश्विक प्रवृत्तियां

मंदी से पहले की अवधि में सीमापारीय प्रवाहों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी और यह प्रचुरता 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट तक बनी रही। 2003 और 2007 के बीच, वैश्विक एफडीआई प्रवाह लगभग चार गुना बढ़े और इसी अवधि में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के प्रवाह लगभग तीन गुना बढ़े। 2007 में 2.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद वैश्विक

एफडीआई प्रवाहों में अगले दो वर्षों में काफी कमी आई और वे 2009 में 1.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गए जिसका कारण था वैश्विक वित्तीय संकट। दूसरी ओर, विकासशील देशों को एफडीआई प्रवाह 2007 के 565 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2008 में 630 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए और 2009 में कम होकर 478 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गए।

2009 के दौरान वैश्विक एफडीआई में गिरावट का मुख्य कारण सीमापारीय विलयन और अधिग्रहण में नरमी तथा विदेशी सहयोगियों के लिए कम प्रतिलाभ की संभावना थी जिसने इक्विटी निवेश तथा पुनर्निवेशित आय को प्रभावित किया। यूएनसीटीएडी के अनुसार, विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों में गिरावट होने का कारण शेयर बाजारों में उथल-पुथल था जिससे मूल्य के संकेत अस्पष्ट हो गए थे जिन पर विलयन और अधिग्रहण निर्भर रहता है। ग्रीन फील्ड निवेश, विशेष रूप से कारोबार और वित्तीय सेवाओं से संबंधित, मामलों में भी कमी आयी।

संस्थागत दृष्टि से, निजी इक्विटी निधियों द्वारा एफडीआई में गिरावट आयी क्योंकि निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण उनका निधि संग्रह कम हो गया था और ऋण बाजार की स्थिति में गिरावट के अनुरूप लीवरेज्ड बायआउट मार्केट में भारी गिरावट हुई थी। दूसरी ओर, 2009 से सोवरेन वेल्थ फंड से एफडीआई में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका स्पष्ट कारण सोवरेन वेल्थ फंड की संशोधित निवेश रणनीति थी - जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से दूर होकर प्राथमिक और विनिर्माण क्षेत्र की ओर जा रही है और जो वित्तीय बाजार की घटनाओं के प्रति कम संवेदनशील है तथा एशिया पर अधिक केंद्रित है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार निरंतर अनिश्चित और कमजोर बना हुआ था, अतः 2010 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह 1.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थिर रहा। यूएनसीटीएडी के ग्लोबल इनवेस्टमेंट ट्रेन्ड्स मॉनिटर (17 जनवरी 2011 को जारी) के अनुसार, वैश्विक एफडीआई प्रवाह समग्र स्तर पर स्थिर बने रहने के बावजूद उनमें क्षेत्र-वार असमान प्रवृत्ति देखी गई - जहां ये उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 7 प्रतिशत पर संकेन्द्रित हुए थे, वहीं लेटिन अमरीका और एशिया के अनेक देशों में एफडीआई प्रवाहों में व्यापक उछाल से प्रेरित होकर समूह के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में एफडीआई प्रवाहों में लगभग 10 प्रतिशत सुधार हुआ। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर एफडीआई प्रवाहों में उछाल का कारण कारपोरेट लाभप्रदता में सुधार और विलयन तथा अधिग्रहण कार्यों में कुछ सुधार था जिसमें शेयर बाजारों में आस्तियों

के मूल्यांकन में सुधार हुआ था और संभाव्य क्रेताओं की वित्तीय क्षमता में वृद्धि हुई थी।

समष्टिआर्थिकस्थिति, विशेषरूपसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हुआ सुधार जिससे कारपोरेट लाभ में वृद्धि हुई और साथ ही शेयर बाजार में बेहतर मूल्यांकन और बढ़ते कारोबारी विश्वास के कारण वैश्विक एफडीआई की संभावना में सुधार हुआ है। यूएनसीटीएडी के अनुसार, इन अनुकूल घटनाओं के कारण नकदी की होल्डिंग के एमएनसी के रेकार्ड स्तर (विकसित देशों की फर्मों में ही 4-5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का अनुमान) से 2011 के दौरान नए निवेशों में परिवर्तित होने में सहायता मिलेगी। विकसित देशों का हिस्सा, जो कि अब कुल एफडीआई अंतर्वाहों के 50 प्रतिशत से अधिक है, वृद्धि की मजबूत संभावनाओं के आधार पर और बढ़ सकता है। किंतु, मुद्रा की घट-बढ़, सरकारी ऋण की समस्या और संभाव्य संरक्षणवादी नीतियां इस सकारात्मक स्थिति के लिए कुछ जोखिम बन सकती हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था (जनवरी 2011) के अनुसार, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को निवल एफडीआई प्रवाह में 2011 में 11 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। चुनिंदा देशों को एफडीआई प्रवाह सारणी 1 में दिया गया है।

## भाग 1.2: भारत में एफडीआई अंतर्वाह की प्रवृत्ति

2008 की संकटपूर्व स्थिति के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को निवल एफडीआई प्रवाह तीन गुना हो जाने से भारत को भी इसके मजबूत देशी आर्थिक निष्पादन के अनुरूप व्यापक एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ। पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत का आकर्षण भारत को प्राप्त एफडीआई प्रवाह में व्यापक वृद्धि से सिद्ध हो जाता है जो कि 2001-02 के लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2008-09 में लगभग 38 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत को प्राप्त एफडीआई प्रवाह में व्यापक वृद्धि ने 1990 के दशक के प्रारंभ से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और साथ ही पूंजी खाते के क्रमिक उदारीकरण का प्रभाव दर्शाया। पूंजी खाते के उदारीकरण के एक भाग के रूप में, रणनीतिक महत्त्व के आधार पर कुछ को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में एफडीआई की क्रमिक रूप से अनुमति दी गई बशर्ते क्षेत्र-विशेष के नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाए। व्यापक और स्थिर एफडीआई प्रवाह ने काफी समय से चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण किया है। हाल के वैश्विक संकट के दौरान जब 2009-10 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह काफी कम हो गया था, तब भारत को एफडीआई प्रवाह में गिरावट तुलनात्मक रूप से कम थी जो कि

**सारणी 1: 2010 में एफडीआई अंतर्वाहों के भारत से अधिक अनुमानित स्तर वाले देश**

	राशि (बिलियन अमरीकी डॉलर)				घट-बढ़ (प्रतिशत)		
	2007	2008	2009	2010 (अनुमान)	2008	2009	2010 (अनुमान)
<b>विश्व</b>	<b>2100.0</b>	<b>1770.9</b>	<b>1114.2</b>	<b>1122.0</b>	<b>-15.7</b>	<b>-37.1</b>	<b>0.7</b>
<b>विकसित अर्थव्यवस्थाएं</b>	<b>1444.1</b>	<b>1018.3</b>	<b>565.9</b>	<b>526.6</b>	<b>-29.5</b>	<b>-44.4</b>	<b>-6.9</b>
अमरीका	266.0	324.6	129.9	186.1	22.0	-60.0	43.3
फ्रांस	96.2	62.3	59.6	57.4	-35.2	-4.3	-3.7
बेल्जियम	118.4	110.0	33.8	50.5	-7.1	-69.3	49.4
यूके	186.4	91.5	45.7	46.2	-50.9	-50.1	1.1
जर्मनी	76.5	24.4	35.6	34.4	-68.1	45.9	-3.4
<b>विकासशील अर्थव्यवस्थाएं</b>	<b>564.9</b>	<b>630.0</b>	<b>478.3</b>	<b>524.8</b>	<b>11.5</b>	<b>-24.1</b>	<b>9.7</b>
चीन	83.5	108.3	95.0	101.0	29.7	-12.3	6.3
हांगकांग	54.3	59.6	48.4	62.6	9.8	-18.8	29.3
रूसी संघ	55.1	75.5	38.7	39.7	37.0	-48.7	2.6
सिंगापुर	35.8	10.9	16.8	37.4	-69.6	54.1	122.6
सऊदी अरब	22.8	38.2	35.5	-	67.5	-7.1	-
ब्राजील	34.6	45.1	25.9	30.2	30.3	-42.6	16.6
<b>भारत</b>	<b>25.0</b>	<b>40.4</b>	<b>34.6</b>	<b>23.7</b>	<b>61.6</b>	<b>-14.4</b>	<b>-31.5</b>

स्रोत: वैश्विक निवेश रिपोर्ट, 2010 और वैश्विक निवेश प्रवृत्ति मॉनिटर, यूएनसीटीएडी।

वैश्विक सुधार से पहले देशी वृद्धि में तेज उछाल और पुनर्निवेशित आय (लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा) में निरंतरता के कारण इक्विटी प्रवाह में मजबूती दर्शाता है जो कि भारत में विदेशी कंपनियों की बेहतर लाभप्रदता को प्रकट करता है। किंतु, जब वैश्विक एफडीआई प्रवाह में कुछ सुधार हुआ और विशेष रूप से जो एशियन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को हुए प्रवाह से प्रभावित था, तब 2010-11 के दौरान भारत को हुए सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में काफी कमी आई। भारत को हुआ सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 2010-11 में कम होकर 20.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया जो कि पिछले वर्ष 27.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

क्षेत्र-वार दृष्टि से, भारत में एफडीआई मुख्यतः सेवा क्षेत्र में जाती है (पिछले पांच वर्षों में 41 प्रतिशत औसत हिस्सा) जिसके बाद विनिर्माण (लगभग 23 प्रतिशत) का स्थान था जो कि मुख्यतः मॉरिशस के माध्यम से हुआ था (पिछले पांच वर्षों में 43 प्रतिशत औसत हिस्सा) जिसके बाद सिंगापुर (लगभग 11 प्रतिशत) का स्थान था। किंतु वर्षों में सेवाओं का हिस्सा 2006-07 के 57 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 30 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि में विनिर्माण और अन्य, जिसमें मुख्यतः बिजली तथा अन्य बिजली उत्पादन शामिल होते हैं, का हिस्सा बढ़ गया (सारणी 2)। भारत में एफडीआई प्रवाह की हाल की प्रवृत्ति पर क्षेत्र-वार जानकारी दर्शाती है कि 2010-11 के दौरान सकल इक्विटी एफडीआई प्रवाह में गिरावट का मुख्य कारण विनिर्माण, स्थावर संपदा और खनन जैसे

क्षेत्रों और कारोबार और वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाएं थीं। विनिर्माण, जिसे भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, में भी कुछ गिरावट आई (सारणी 2)।

## भाग 2: एफडीआई नीति की संरचना

नीतिगत व्यवस्था भी एक प्रमुख कारक होती है जो किसी भी देश में निवेश प्रवाहों को प्रभावित करती है। समष्टि मूल तत्वों को रेखांकित करने के अलावा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने की किसी देश की क्षमता उसकी नीतिगत व्यवस्था पर निर्भर करती है - कि वह विदेशी निवेश प्रवाहों को प्रोत्साहन देता है या हतोत्साहित करता है। इस भाग में भारत के एफडीआई की नीतिगत संरचना की समीक्षा की गई है और भारत की नीति और चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना की गई है।

### 2.1 भारत में एफडीआई नीतिगत संरचना

विदेशी निवेश के प्रति भारत के दृष्टिकोण में 1990 के दशक से व्यापक परिवर्तन हुआ है जब इसने संरचनात्मक आर्थिक सुधार शुरू किए जिसमें अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र कवर किए गए थे।

#### उदारीकरण से पहले की अवधि

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने औद्योगीकरण की आयात-प्रतिस्थापन रणनीति के प्रभुत्व को देखते हुए एफडीआई

## सारणी 2: भारत में इक्विटी एफडीआई अंतर्वाह

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>क्षेत्रवार हिस्सा (प्रतिशत)</b>					
विनिर्माण	17.6	19.2	21.0	22.9	32.1
सेवाएं	56.9	41.2	45.1	32.8	30.1
निर्माण, स्थावर संपदा और खनन	15.5	22.4	18.6	26.6	17.6
अन्य	9.9	17.2	15.2	17.7	20.1
<b>कुल</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>इक्विटी अंतर्वाह ( बिलियन अमरीकी डॉलर )</b>					
विनिर्माण	1.6	3.7	4.8	5.1	4.8
सेवाएं	5.3	8.0	10.2	7.4	4.5
निर्माण, स्थावर संपदा और खनन	1.4	4.3	4.2	6.0	2.6
अन्य	0.9	3.3	3.4	4.0	3.0
<b>कुल इक्विटी एफडीआई</b>	<b>9.3</b>	<b>19.4</b>	<b>22.7</b>	<b>22.5</b>	<b>14.9</b>

नीति बनाते समय अत्यधिक सावधान और चयनित दृष्टिकोण अपनाया। स्व-निर्भर बनने की दृष्टि से, नीतिगत लक्ष्य का दोहरा स्वरूप था - विदेशी सहयोग के माध्यम से एफडीआई का स्वागत उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया गया और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा देशी उद्योगों के संरक्षण और पोषण के लिए निम्न प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया। विनियामक संरचना को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के माध्यम से सुदृढ़ किया गया जिसमें किसी संयुक्त उद्यम में विदेशी इक्विटी की धारिता की 40 प्रतिशत तक ही अनुमति दी गई थी। बाद में, विभिन्न शिथिलताएं निर्यात उन्मुख कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों तक और उच्च प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक बढ़ाई गई थीं जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी धारिता की अनुमति शामिल है। इसके अलावा, एशिया के अन्य देशों की सफलता के अनुभवों के आधार पर सरकार ने न केवल विशेष आर्थिक अंचलों (सेज) की स्थापना की बल्कि उदार नीति की रचना की और निर्यात संवर्धन के लिए इन अंचलों में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराए। चूंकि भारत निरंतर अत्यधिक संरक्षणात्मक रहा है, इन उपायों से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को अधिक लाभ नहीं हुआ। इन सीमाओं को पहचानते हुए, ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन्स के माध्यम से निर्यातों की मार्केटिंग, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और आधुनिकीकरण बढ़ाने की दृष्टि से 1980 के दशक में व्यापार और निवेश नीति में आंशिक उदारीकरण किया गया। औद्योगिक नीति की घोषणा (1980 और 1982) तथा प्रौद्योगिकी नीति (1983) से नीतिगत दिशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में विदेशी निवेश के प्रति उदार दृष्टिकोण

सामने आया। इस नीति की विशेषता कुछ औद्योगिक नियमों से लाइसेंसिकरण हटाना और भारतीय विनिर्माण निर्यातों को प्रोत्साहित करना और साथ ही पूंजीगत सामान और प्रौद्योगिकी के उदारीकृत आयात के माध्यम से उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल देना था। इसे प्रशुल्क में कटौती और अनेक मदों को आयात लाइसेंसिकरण से हटाकर खुले सामान्य लाइसेंसिकरण में लाने के रूप में व्यापार उदारीकरण उपायों से सहायता मिली थी।

**उदारीकरण के बाद की अवधि**

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब हुआ जब भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण और सुधार का कार्यक्रम अपनाया जिसका लक्ष्य अपनी वृद्धि की संभावना बढ़ाना और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय साधना था। औद्योगिक नीतिगत सुधारों ने एक ओर तो निवेश परियोजनाओं और कारोबार विस्तार पर लगे प्रतिबंधों को क्रमिक रूप से हटाया और दूसरी ओर विदेशी प्रौद्योगिकी और निधीयन तक पहुंच बढ़ाने की अनुमति दी। विदेशी निवेश के उदारीकरण संबंधी उपायों की श्रृंखला में निम्न बातें शामिल थीं: (i) एफडीआई के दोहरे अनुमोदन मार्ग की शुरुआत - भारतीय रिजर्व बैंक स्वचालित मार्ग और सरकार का अनुमोदन (एसआईए/एफआईपीबी) मार्ग, (ii) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रौद्योगिकीय समझौते के लिए स्वतः अनुमति, (iii) अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय कारपोरेट निकायों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति, (iv) वर्तमान कंपनियों के लिए विदेशी इक्विटी सहभागिता की सीमा बढ़ाकर 51 प्रतिशत करना और विदेशी ब्रांड नाम के उपयोग का उदारीकरण और (v) विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की परंपरा पर हस्ताक्षर करना। इन प्रयासों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (जिसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 को प्रतिस्थापित किया), जो कि कम कड़ा था, के अधिनियमन से बढ़ावा मिला। इस एक प्रयास ने वित्तीय क्षेत्र के अनुक्रमिक सुधारों के साथ भारत में पूंजी खाते के अधिक उदारीकरण का मार्ग बनाया।

स्व-चालित मार्ग के तहत के निवेश प्रस्तावों और फेमा से संबंधित मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है जबकि अनुमोदन मार्ग के माध्यम से निवेश और एफडीआई नीति संबंधी मामलों पर सरकार अपनी तीन संस्थाओं, नामतः विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, औद्योगिक सहायता सचिवालय और विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करती है।

स्व-चालित मार्ग के तहत एफडीआई के लिए सरकार या रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। निवेशकों के लिए मात्र यह आवश्यक होता है कि वे आवक प्रेषण की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होता है और उक्त कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज विदेशी निवेशक को शेषों के निर्गम से 30 दिन के भीतर फाइल करने होते हैं। अनुमोदन मार्ग के तहत, प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विचार करता है। संयुक्त प्रस्तावों, जिनमें विदेशी निवेश/विदेशी तकनीकी सहयोग शामिल होते हैं, के लिए अनुमोदन भी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। क्षेत्र विशेष की सीमाओं के संदर्भ में वर्तमान एफडीआई नीति का सारांश सारणी 3 में दिया गया है:

**सारणी 3: भारत में विदेशी निवेश की क्षेत्र विशेष संबंधी सीमाएं**

क्षेत्र	एफडीआई कैप/इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य स्थिति
<b>क. कृषि</b>			
1. पुष्प कृषि, बागवानी, बीजों का विकास और उत्पादन, पशु पालन, मत्स्य पालन, जलजीव पालन, साग तथा मशरूम कृषि और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं	100%	स्वचालित	
2. प्लान्टेशन सहित चाय क्षेत्र	100%	एफआईपीबी	
<i>(किसी भी अन्य कृषि क्षेत्र कार्य में एफडीआई की अनुमति नहीं है)</i>			
<b>ख. उद्योग</b>			
1. उत्खनन सहित खनन और हीरों तथा मूल्यवान पत्थरों का खनन; स्वर्ण, रजत और खनीज पदार्थ।	100%	स्वचालित	
2. बिजली परियोजनाओं द्वारा सीमित उपयोग के लिए कोयला और लिग्नाइट का खनन और लोहा तथा इस्पात, सीमेंट उत्पादन।	100%	स्वचालित	
3. टाइटेनियमयुक्त खनिज का खनन और खनिज अलग करना।	100%	एफआईपीबी	
<b>ग. विनिर्माण</b>			
1. एल्कोहल - आसवन और मद्यकरण	100%	स्वचालित	
2. कॉफी और रबर प्रसंस्करण तथा वेयरहाउसिंग	100%	स्वचालित	
3. रक्षा उत्पादन	26%	एफआईपीबी	
4. हानिकारक रसायन और आइसोसाइनेट	100%	स्वचालित	
5. औद्योगिक विस्फोटक - विनिर्माण	100%	स्वचालित	
6. ड्रग्स और औषधि	100%	स्वचालित	
7. उत्पादन सहित बिजली (अणु ऊर्जा छोड़कर), प्रेषण, वितरण और पॉवर ट्रेडिंग।	100%	स्वचालित	
<i>(आणविक बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली/अणु ऊर्जा के उत्पादन, प्रेषण और वितरण के लिए एफडीआई की अनुमति नहीं है क्योंकि इस कार्य में निजी निवेश प्रतिबंधित है और यह सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है)।</i>			
<b>घ. सेवाएं</b>			
1. नागर उड्डयन	100%	स्वचालित	
क. ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	74 % से अधिक	
ख. विद्यमान परियोजनाएं			
2. अस्तित्व पुनर्निर्माण कंपनियां	49%	एफआईपीबी	
3. बैंकिंग			
क. निजी क्षेत्र	74% (एफडीआई+एफआईपीबी)। एफआईआई 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए	स्वचालित	
ख. सरकारी क्षेत्र	20%		



## सारणी 3: भारत में विदेशी निवेश की क्षेत्र विशेष संबंधी सीमाएं (समाप्त)

4. एनबीएफसी: मर्चेन्ट बैंकिंग हामीदारी, संविभागीय प्रबंध सेवाएं, निवेश परामर्शी सेवाएं, वित्तीय परामर्श, स्टॉक ब्रोकिंग, आस्ति प्रबंध, उद्यम पूंजी, अभिरक्षक, फैक्ट्रिंग, पट्टेदारी और वित्त, आवास वित्त, विदेशी मुद्रा ब्रोकिंग, आदि।	100%	स्वचालित	न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों की शर्त पर
5. प्रसारण			
क. एफएम रेडियो	20%	एफआईपीबी	
ख. केबल नेटवर्क;	49% (एफडीआई+एफआईआई)	एफआईपीबी	
ग. डाइरेक्ट टू होम;	100%	एफआईपीबी	
घ. अप-लिकिंग, एचयूबी जैसी हार्डवेयर सुविधाओं की स्थापना	49%	एफआईपीबी	
ड. समाचार की अप-लिकिंग और करंट अफेयर टीवी चैनल	26%	एफआईपीबी	
6. पण्य विनिमय	49% (एफडीआई+एफआईआई) (एफडीआई 26% एफआईआई 23%)	एफआईपीबी	
7. बीमा	26%	स्वचालित	आईआरडीए से क्लियरेंस
8. पेट्रोलियम और नैसर्गिक वायु:			
क. रिफाइनरी	49% (पीएसयू). 100% (निजी कंपनियों)	एफआईपीबी (पीएसयू के लिए) स्वचालित (निजी)	
9. प्रिंट मीडिया			
क. समाचारपत्रों और समाचारों तथा वर्तमान घटनाएं छापने वाली आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन
ख. वैज्ञानिक पत्रिकाओं/विशिष्ट जर्नल्स/आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	100%	एफआईपीबी	
10. दूरसंचार			
क. बेसिक और सेल्युलर, यूनिफाइड एक्सेस सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी, वी-सैंट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सर्विसेस (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विसेस (जीएमपीसीएस) और अन्य।	74 % (एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर/जोडीआर, परिवर्तनीय शेयर आदि सहित)	49 % तक स्वचालित और 49 % से आगे एफआईपीबी	

## निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई पर प्रतिबंध है

- खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद की खुदरा बिक्री को छोड़कर);
- अणु ऊर्जा;
- सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार;
- कैसिनो आदि सहित जुआ और शर्त लगाना;
- चिट फंड कारोबार;
- निधि कंपनी;
- अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) का व्यापार;
- निजी क्षेत्र के निवेश के लिए न खोले गए कार्य/क्षेत्र;
- कृषि (नियंत्रित स्थिति में पुष्प कृषि, बागवानी, बीजों का विकास, पशु पालन, मत्स्य पालन और साग तथा मशरूम कृषि और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं छोड़कर) और प्लानटेशन (चाय प्लानटेशन छोड़कर);
- स्थावर संपदा कारोबार, या फार्म हाउसों का निर्माण; तंबाकू या तंबाकू जैसी सामग्री से सिगार, चुरट, सिगारिलोज और सिगारेटों का निर्माण।

## 2.2 एफडीआई नीति: अंतरराष्ट्रीय अनुभव

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को पूंजी और प्रौद्योगिकी के अंतरण को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली माना जाता है और इस प्रकार मेजबान देशों में आर्थिक वृद्धि के प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय निगम एफडीआई को अपनी कारपोरेट रणनीतियों और मेजबान देशों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अनुरूप अपने सीमापारीय उत्पादन कार्यों

के पुनर्संगठन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं। यह विचार पिछले कुछ दशकों और विशेष रूप से आठवें दशक से विदेशों से निवेश प्रवाहों के प्रति उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के आकलन और दृष्टि में प्रमुख प्रेरक घटक रहे हैं। इस भाग में चुनिंदा देशों की एफडीआई नीतियों की समीक्षा की गई है ताकि भारत में एफडीआई नीति पर विचार करने के लिए इस समय "भारत की स्थिति क्या है" विषय पर जानकारी इकट्ठी की जा सके।

## चीन

- एफडीआई को प्रोत्साहित करना चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। उसने विदेशी कारोबार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से खोला है और एफडीआई को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया है।
- सरकारी नीतियों में विदेशी मुद्रा के प्रयोग और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना तथा खुले शहरों के माध्यम से संयुक्त उद्यमों को अनुमति देने के लिए नए विनियमन बनाए गए। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की धारणा 1984 में और चौदह कोस्टल शहरों पर लागू की गयी। 1986 में अनुकूल विनियमन और प्रावधानों का प्रयोग किया गया ताकि एफडीआई अंतर्वाहों को प्रोत्साहित किया जा सके, विशेष रूप से यह कार्य निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यमों और संयुक्त उद्यमों में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया।
- विदेशी संयुक्त उद्यमों को 1986 में अधिमानी कर व्यवहार, सामग्री और उपकरण जैसी निविष्टियों के आयात की स्वतंत्रता, विदेशी मुद्रा रखने और एक-दूसरे के साथ उसकी अदला-बदली करने का अधिकार और सरल लाइसेंसिकरण प्रक्रिया उपलब्ध करायी गयी। निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यमों और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने वाले उद्यमों को अतिरिक्त कर-लाभ दिया गया।
- कृषि, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, आधारभूत कच्चा माल, उच्च प्रौद्योगिकीयुक्त उद्योगों और उन एफडीआई परियोजनाओं के लिए एफडीआई को प्राथमिकता दी गई जो मध्य तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में नैसर्गिक संसाधनों और तुलनात्मक रूप से कम श्रम लागत का लाभ ले सके।
- एफडीआई के प्रति चीन की नीतियों में मोटे तौर पर तीन चरण देखे गए: क्रमिक और सीमित खुलापन, अधिमानी व्यवहार के माध्यम से सक्रिय प्रोत्साहन और देशी औद्योगिक लक्ष्यों के अनुरूप एफडीआई को प्रोत्साहन।

## चिली

- चिली में, विदेशी निवेश संबंधी नीतिगत संरचना, जो कि संविधान तथा विदेशी निवेश विधान में अंतर्भूत है, काफी स्थिर और पारदर्शी है और एफडीआई को सुगम करने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस संरचना के तहत निवेशक इंडिविजुअल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए

स्टेट के साथ कानूनी संविदा पर हस्ताक्षर करता है और बदले में अनेक विशिष्ट गारंटियां और अधिकार प्राप्त करता है।

- चिली में कोई विदेशी निवेशक चिली आधारित कंपनी का 100 प्रतिशत तक का स्वामी बन सकता है और संपत्ति के अधिकार पर कोई समय-सीमा नहीं होती। उनकी पहुंच कोस्टल व्यापार, वायु परिवहन और मास मीडिया सहित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक गतिविधियों और क्षेत्रों तक होती है।
- चिली ने खनन, सेवा, बिजली, गैस और जल उद्योग तथा विनिर्माण में निवेश आकर्षित किया।
- निवेशकों को इस गारंटी का अधिकार दिया गया कि वे पूंजी का प्रत्यावर्तन उसके प्रवेश के एक वर्ष बाद तथा लाभ का प्रेषण कभी भी कर सकते हैं।
- चिली का संविधान भेदभाव विरोधी सिद्धांत पर आधारित होने के बावजूद विदेशी निवेशकों को कर में कुछ लाभ दिए गए हैं जैसे कि आय-कर व्यवस्था की अपरिवर्तनीयता, परोक्ष करों की अपरिवर्तनीयता और बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष नीतिगत व्यवस्था।

## मलेशिया

- मलेशिया की एफडीआई प्रणाली में इस बात का कड़ाई से विनियमन किया जाता है कि विदेशी विनिर्माण कार्यों का लाइसेंसिकरण होना ही चाहिए भले ही उनके कारोबार का स्वरूप कुछ भी हो।
- 1998 तक, विदेशी इक्विटी शेयर की सीमा सशर्त थी जिसका आधार निष्पादन और समयानुसार औद्योगिक नीति द्वारा निर्धारित शर्तें थीं।
- पहले, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी इक्विटी शेयर की सीमा का आधार देश की निर्यातोन्मुख नीति के समर्थनार्थ निर्यात किए गए उत्पादों के हिस्सा था।
- न्यूनतम 80 प्रतिशत निर्यात करने वाली एफडीआई परियोजनाएं या उन्नत प्रौद्योगिकी से युक्त उत्पादन को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और इक्विटी संबंधी कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती। 1997-98 के संकट के बाद, प्रतिबंध हटा दिया गया क्योंकि देश को एफडीआई की आवश्यकता थी।

### कोरिया

- कोरिया की सरकार ने एक अलग विदेशी निवेश नीति बनाए रखी जिसमें औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में देशी बचत के कम स्तर के अनुपूरण के लिए प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में ऋण को प्राथमिकता दी गई। कोरिया की निवेश आवश्यकता के लिए विदेशी उधार पर अत्यधिक निर्भरता अन्य देशों से एकदम विपरीत है।
- कोरिया की सरकार ने एफडीआई और विदेशी लाइसेंसिकरण दोनों पर प्रतिबंध लगाते हुए औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए विदेशी प्रौद्योगिकी के देशीकरण और अवशोषक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इससे कोरियाई फर्मों को आयातित प्रौद्योगिकी का लाभ लेने में सहायता मिली जिससे अंततः सामसंग, हुंडई और एलजी जैसे वैश्विक ब्रांड उभरे।
- कोरिया की सरकार ने 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद उदारीकृत एफडीआई नीति की प्रणाली अपनायी ताकि स्टैंडबाय ऋण के लिए विनिमय में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्त पूरी की जा सके।
- संकट के तत्काल बाद कोरिया में अनेक नई संस्थाएं अस्तित्व में आईं। "इन्वेस्ट कोरिया" कोरिया की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है जो एफडीआई को आकर्षित करने के साधन के रूप में वन-स्टॉप सेवा उपलब्ध कराती है जबकि निवेश लोकपाल कार्यालय की स्थापना कोरिया में विदेशी निवेश कंपनियों को आफ्टर-केयर सेवा उपलब्ध कराने के लिए की गयी थी।
- कोरिया में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिसमें कर में छूट और कटौती, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता, आर एंड डी परियोजनाओं के लिए नकदी अनुदान और विशिष्ट अवधि के लिए कारखानों और कारोबारी परिचालनों के लिए भूमि की पट्टा-लागत से छूट देना या उसे कम करना शामिल है, 1998 में एक नया विदेशी निवेश प्रोत्साहन अधिनियम अधिनियमित किया गया।
- कोरिया में निर्माण प्रक्रिया में विलंब का प्रमुख कारण प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सांस्कृतिक असर की जांच-पड़ताल बतलाया जाता है (ओईसीडी, 2008)।

### थाईलैंड

- थाईलैंड में पारंपरिक आयात-प्रतिस्थापन रणनीति अपनायी गयी जिसमें 1960 के दशक में आयातों पर और विशेष रूप

से तैयार माल पर प्रशुल्क लगाया गया। सरकारी उद्यमों की भूमिका 1950 के दशक से काफी कम की गयी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया गया। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक संस्थागत प्रणाली के पोषण पर ध्यान दिया गया। निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 1970 के दशक के प्रारंभ में प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया की सहायता के लिए अधिकतर घटक, कच्चा माल और मशीनरी का आयात करने की जरूरत के चलते भुगतान संतुलन की समस्या आ गयी थी।

- एफडीआई के संदर्भ में, 1977 में एक नया निवेश प्रोत्साहन अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत निवेश बोर्ड गठित किया गया, जिसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने और निजी निवेशकों द्वारा महसूस की गयी बाधाएं हटाने के अधिकार प्राप्त थे (सारणी 4)। पूर्व एशियाई वित्तीय संकट के बाद थाई सरकार ने एफडीआई के संदर्भ में अधिक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया और औद्योगिक आधार बढ़ाने और विशिष्ट आर्थिक कार्यों में विदेशी स्वामित्व में बाधा बने हुए कानून तथा विनियमों को शिथिल करने और निर्यात के संबंध में अनेक कदम उठाए।
- 1972 में अधिनियमित एलीयन बिजनेस कानून से कुछ कार्यों में अधिक विदेशी स्वामित्व को प्रतिबंधित किया गया था। इस कानून को 1999 में संशोधित किया गया। नए कानून के अनुसार कानून, रेखांकन, विज्ञापन और अधिकतर प्रकार के निर्माण जैसे अनेक व्यवसायों में विदेशी सहभागिता की सीमा शिथिल की गयी और उक्त मर्दों को पूर्णतः प्रतिबंधित सूची से हटाकर कम प्रतिबंधित सूची में रखा गया।

समापन के रूप में, एफडीआई को आकर्षित करने में चीन को मिली भारी सफलता का श्रेय उसकी सक्रिय एफडीआई नीति को दिया जा सकता है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना भी शामिल है, जिसमें विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करना और कम श्रम लागत के कारण तुलनात्मक लाभ शामिल है। ऊपर दिये अनुसार चुनिंदा उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनायी गयी एफडीआई नीतियों की तुलना से पता चलता है कि ये नीतियां लक्ष्य, विनियामक संरचना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन और निर्यात संवर्धन पर फोकस के संदर्भ में सामान्यतः एक जैसी हैं किंतु प्रोत्साहन की संरचना और कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंधों में देश-वार भिन्नता है। जहां चीन और कोरिया विदेशी निवेशकों को स्पष्ट कर प्रोत्साहन मुहैया कराते हैं, वहीं अन्य देश



कर संबंधी कानूनों की स्थिरता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी प्रकार, जहां सभी देश विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं चीन में कृषि क्षेत्र के लिए भी छूट दी जाती है। किंतु, यह स्पष्ट है कि नीतियों में देश-वार विशेष बातों के संदर्भ में भिन्नता होने के बावजूद विदेशी निवेश को सामान्यतः सभी देशों में प्रोत्साहन दिया जाता है (सारणी 4)।

### 2.3 एफडीआई नीतियों की देश-वार तुलना - भारत की स्थिति कैसी है?

देश-वार भिन्न नीतियों को संक्षिप्त रूप में लाकर एक सामान्य तुलनीय सूची या माप बनायी जाए तो नीतियों की वास्तविक तुलना की जा सकती है। अतः एफडीआई नीतिगत संरचना के संदर्भ में

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति की जांच और विश्लेषण के लिए इस खंड में विश्व बैंक द्वारा 2009 में 87 अर्थव्यवस्थाओं के लिए किए गए सर्वेक्षण के परिणाम, जो कि "इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर्स" नामक उसके अंतिम प्रकाशन में प्रकाशित किए गए थे, को आधार बनाया गया है।

सर्वेक्षण में चार संकेतकों अर्थात् "इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर्स", "स्टारटिंग अ फॉरेन बिजनेस", "अक्सेसिंग इंडस्ट्रीयल लैंड" और "आरबिट्रेटिंग कमर्शियल डिस्पुट्स" पर विचार किया गया ताकि किसी विशेष देश में एफडीआई संबंधी आकलन उपलब्ध कराया जा सके। "इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर्स" संकेतक में उस स्तर को मापा जाता है जिस पर देशी कानून विदेशी कंपनियों को फर्म की स्थापना या स्थानीय फर्म के अधिग्रहण की अनुमति देता है। "स्टारटिंग अ फॉरेन

सारणी 4: चुनिंदा देशों में एफडीआई नीति और संस्थागत संरचना

	उदारीकरण का वर्ष	लक्ष्य	प्रोत्साहन	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	विशेषताएं
चीन	1979	पारंपरिक कृषि में परिवर्तन, औद्योगिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा और निर्यात संवर्धन।	अधिमानी कर व्यवहार के साथ विदेशी संयुक्त उद्यम उपलब्ध कराए गए। निर्यातनुमुख संयुक्त उद्यमों और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने वाले उद्यमों को अतिरिक्त कर लाभ। जल आपूर्तिकर्ता, बिजली और परिवहन (राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों जैसे मूल्य का भुगतान) और ब्याज-मुक्त आरएमबी ऋणों तक अधिमानी पहुंच उपलब्ध कराई गई।	कृषि, ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, आधारभूत कच्चा माल और उच्च प्रौद्योगिकीयुक्त उद्योग।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना।
चिली	1974	प्रौद्योगिकी अंतरण, निर्यात संवर्धन और देशी प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाना।	कर व्यवस्था की अपरिवर्तनीयता से कर प्रणाली में स्थिरता की संभावना।	सभी उत्पादक गतिविधियां और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कोस्टल व्यापार, हवाई परिवहन और मास मीडिया छोड़कर।	विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन का सहारा नहीं लिया जाता।
कोरिया	1998	अवशोषक क्षमता को प्रोत्साहन और एफडीआई और विदेशी लाइसेंसिकरण को सीमित रखते हुए औद्योगिकरण के प्रारंभ में रिवर्स इंजीनीयरिंग के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकी का देशीकरण	विदेशी निवेश क्षेत्र में स्थित कारोबारों को प्रारंभिक लाभ की शुरुआत के वर्ष से पांच वर्षों तक कंपनी आय कर से पूरी छूट मिलती है और बाद के दो वर्षों में 50 प्रतिशत की कटौती मिलती है। मुक्त आर्थिक क्षेत्रों में हार्ड-टेक विदेशी निवेश तीन वर्ष तक पूरी तथा बाद के दो वर्षों में 50 प्रतिशत छूट के लिए पात्र होते हैं। हार्ड-टेक ग्रीन फिल्ड निवेश को नकदी अनुदान और आर एंड डी निवेश सरकारी अनुमोदन के तहत होते हैं।	विनिर्माण और सेवाएं	1990 के दशक उत्तरार्ध तक एफडीआई-आधारित विकास रणनीति के लिए ऋण-आधारित उधार।
मलेशिया	1980 का दशक	निर्यात संवर्धन	विशिष्ट कर प्रोत्साहन नहीं।	विनिर्माण और सेवाएं	मलेशियन औद्योगिक विकास प्राधिकरण की पहचान एशियाई क्षेत्र की प्रभावी संस्थाओं में से एक के रूप में की गयी थी।
थाईलैंड	1977	प्रौद्योगिकी अंतरण और निर्यात संवर्धन	विशिष्ट कर प्रोत्साहन नहीं। थाईलैंड निवेश बोर्ड ने एफडीआई को प्रोत्साहन देने के लिए तीन मुख्य श्रेणियों के तहत कार्य किए। 1. छवि निर्माण ताकि यह दर्शाया जा सके कि मेजबान देश एफडीआई के लिए किस प्रकार उपयुक्त स्थान है। 2. विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निवेशकों को प्रवृत्त करके निवेश बढ़ाना। 3. निवेशकों को सेवाएं प्रदान करना।	विनिर्माण और सेवाएं।	-

## सारणी 5 क: इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर - क्षेत्र वार सीमा -2009

देश	खनन, तेल और वायु	कृषि और वानिकी	हल्का विनिर्माण	दूरसंचार	बिजली	बैंकिंग	बीमा	परिवहन	मीडिया	निर्माण, पर्यटन और खुदरा	स्वास्थ्य देखभाल तथा वेस्ट मैनेजमेंट
अर्जेंटीना	100	100	100	100	100	100	100	79.6	30	100	100
ब्राजील	100	100	100	100	100	100	100	68	30	100	50
चिली	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
चीन	75	100	75	49	85.4	62.5	50	49	0	83.3	85
<b>भारत</b>	<b>100</b>	<b>50*</b>	<b>81.5</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>87*</b>	<b>26</b>	<b>59.6</b>	<b>63*</b>	<b>83.7*</b>	<b>100</b>
इंडोनेशिया	97.5	72	68.8	57	95	99	80	49	5	85	82.5
कोरिया लोकतंत्र	100	100	100	49	85.4	100	100	79.6	39.5	100	100
मलेशिया	70	85	100	39.5	30	49	49	100	65	90	65
मेक्सिको	50	49	100	74.5	0	100	49	54.4	24.5	100	100
फिलीपींस	40	40	75	40	65.7	60	100	40	0	100	100
रूसी संघ	100	100	100	100	100	100	49	79.6	75	100	100
दक्षिण अफ्रीका	74	100	100	70	100	100	100	100	60	100	100
थाईलैंड	49	49	87.3	49	49	49	49	49	27.5	66	49

\*: आंकड़ों की सीमा के लिए पैरा देखें।

स्रोत: इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर, विश्व बैंक, 2010.

बिजनेस" संकेतक किसी विदेशी कंपनी की स्थानीय सब्सिडीयरी की स्थापना से संबद्ध समय, क्रियाविधि और विनियमन रेकार्ड करता है। "अक्सेसिंग इंडस्ट्रियल लैंड" संकेतक मेजबान देश में भूमि पट्टे पर लेने या क्रय करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनी के लिए विधिक अभिमताओं, भूखंडों संबंधी उपलब्ध जानकारी और भूमि पट्टे पर लेने संबंधी स्तरों का आकलन करता है। "आरबिट्रेटिंग कमर्शियल डिस्पुट्स" संकेतक विवाद के वैकल्पिक समाधान, विवाचन के नियम और जिस सीमा तक कानूनी सहायता और विवाचन सुविधा मिल

सकती है उसके लिए कानूनी संरचना की शक्ति का आकलन करता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने में भारत से प्रतिस्पर्धा करने वाले 15 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उक्त चार मानदंडों के संदर्भ में भारत की स्थिति सारणी 5क और 5ख में दी गयी है।

इस तुलना से निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां की जा सकती हैं:

- चुनिंदा देशों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और रशियन फेडरेशन जैसे

## सारणी 5 ख : इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर - मुख्य संकेतक -2009

देश अर्थव्यवस्था	विदेशी कारोबार शुरू करना			औद्योगिक भूमि तक पहुंच						वाणिज्यिक विवादों का विवाचन		
	समय (दिन)	क्रियाविधि (संख्या)	स्थापना सुगमता सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	लीज राइट की शक्ति का सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	स्वामित्व अधिकार सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	भूमि सूचना तक पहुंच का सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	भूमि सूचना की उपलब्धता का सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	निजी भूमि पट्टे पर देने का समय (दिन)	सरकारी भूमि पट्टे पर देने का समय (दिन)	विधिक शक्ति सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	क्रियाविधि की सुगमता का सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)	विधिक सहायता के दायरे का सूचकांक (0=न्यून. 100=अधि.)
अर्जेंटीना	50	18	65	79.3	100	44.4	85	48	112	63.5	72.2	55.1
ब्राजील	166	17	62.5	85.7	100	33.3	75	66	180	84.9	45.7	57.2
चिली	29	11	63.2	85.7	100	33.3	80	23	93	94.9	62.8	74.8
चीन	99	18	63.7	96.4	n/a	50	52.5	59	129	94.9	76.1	60.2
<b>भारत</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>76.3</b>	<b>92.9</b>	<b>87.5</b>	<b>15.8</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>295</b>	<b>88.5</b>	<b>67.6</b>	<b>53.4</b>
इंडोनेशिया	86	12	52.6	78.6	n/a	21.4	85	35	81	95.4	81.8	41.3
कोरिया लोकतंत्र	17	11	71.1	85.7	100	68.4	70	10	53	94.9	81.9	70.2
मलेशिया	14	11	60.5	78.5	87.5	23.1	85	96	355	94.9	81.8	66.7
मेक्सिको	31	11	65.8	81.3	100	33.3	90	83	151	79.1	84.7	52.7
फिलीपींस	80	17	57.9	68.8	n/a	23.5	87.5	16	n/a	95.4	87	33.7
रूसी संघ	31	10	68.4	85.7	100	44.4	90	62	231	71.6	76.1	76.6
दक्षिण अफ्रीका	65	8	78.9	84.5	100	47.4	85	42	304	82.4	79	94.5
थाईलैंड	34	9	60.5	80.7	62.5	27.8	70	30	128	84.9	81.8	40.8

स्रोत: इन्वेस्टिंग अक्रॉस बॉर्डर, विश्व बैंक, 2010.

देशों में क्षेत्रवार उच्चतम सीमा भारत की तुलना में अधिक है जो यह दर्शाती है कि उनकी एफडीआई नीति अधिक उदार है।

- चीन में कृषि और वानिकी तथा बीमा को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों में उच्चतम सीमा भारत की तुलना में कम है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि चीन कृषि में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है जबकि मीडिया में इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। दूसरी ओर, भारत में "खनन, तेल और गैस", "बिजली" और "स्वास्थ्य देखभाल और वेस्ट प्रबंधन" जैसे क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी स्वामित्व की अनुमति है।
- "स्टारटिंग अ फॉरेन बिजनेस" संकेतक के संदर्भ में चुनिंदा प्रतिपक्षी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। 2009 में "स्टारटिंग अ फॉरेन बिजनेस" के लिए भारत में लगभग 46 दिन लगे जिसमें 16 क्रियाविधियां थीं जबकि चीन में 99 दिन और 18 क्रियाविधियां और ब्राजील में 166 दिन और 17 क्रियाविधियां थीं (सारणी 5ख)।
- अन्य महत्वपूर्ण संकेतक अर्थात् "अक्सेसिंग इंडस्ट्रीयल लैंड" के संदर्भ में भारत की स्थिति मिश्रित है। जहां लीज अधिकारों और स्वामित्व अधिकारों पर आधारित संकेतकों के संदर्भ में रैंकिंग काफी उच्च है, वहीं निजी और सरकारी भूमि पट्टे पर देने का समय क्रमशः 90 दिन और 295 दिन के साथ चुनिंदा देशों के बीच काफी ऊपर है। चीन में, निजी भूमि पट्टे पर देने में 59 दिन और सरकारी भूमि पट्टे पर देने में 129 दिन लगते हैं। यह विदेशी कंपनियों के निवेश संबंधी निर्णय को काफी प्रभावित करता है।
- "आरबिट्रेटिंग कमर्शियल डिस्पुट्स" संकेतक के संदर्भ में भारत ब्राजील और रशियन फेडरेशन के स्तर पर है। कानूनी सूचकांक की सुदृढ़ता अच्छी है किंतु कानूनी सहायता सूचकांक का दायरा कुछ कम है।

इस प्रकार, भारत और अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की एफडीआई नीति की समीक्षा से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच, लाभांश का प्रत्यावर्तन और इक्विटी के स्वामित्व संबंधी मानदंडों के संदर्भ में भारत का नीतिगत रुझान अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से तुलनीय है, वहीं "निजी भूमि पट्टे पर देने संबंधी समय", "भूमि संबंधी जानकारी तक पहुंच" और "कानूनी सहायता की सीमा" जैसे गुणात्मक मानदंडों संबंधी नीति तुलनात्मक रूप से अधिक पारंपरिक है। किसी परियोजना की स्थापना में लगने वाले समय के कारण लागत बढ़कर

प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है, अतः दूसरे प्रकार से काफी उदार पायी गयी नीतिगत व्यवस्था क्रियाविधिक विलंब के कारण कम प्रतिस्पर्धी या आर्थिक रूप से अक्षम सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार, आर्थिक रूप से अक्षम परियोजना निवेश योग्य निधियों के सीमापारीय प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। किंतु एफडीआई के प्रवाह पर इन गुणात्मक मानदंडों के स्पष्ट प्रभाव का मूल्यांकन करना प्रायोगिक प्रश्न है। निम्नांकित खंड में भारत में एफडीआई के प्रवाह को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के असर के आकलन का एक प्रयास किया गया है।

### धारा 3: भारत में हाल की अवधि में एफडीआई प्रवाह - मजबूत आधार घटकों के बावजूद स्पष्ट गिरावट - स्पष्टीकरण

ऊपर उल्लेख किए अनुसार, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट उभरने के बाद वैश्विक एफडीआई प्रवाह में काफी कमी आ गयी हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और देशों में यह अलग-अलग प्रकार की थी। विकासशील देशों द्वारा प्रारंभ में कुछ आघात-सहनीयता दिखाने के बावजूद अंततः व्यापार, वित्तीय और विश्वास चैनलों के माध्यम से संकट का विस्तार होता गया और 2009 में उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह कम हो गया। बाद में, जहां उन्नत देशों को एफडीआई प्रवाह निरंतर कम होता गया, वहीं अनेक लैटिन अमरीकी और एशियन देशों को एफडीआई प्रवाह 2010 के दौरान काफी बढ़ गया जिसका कारण कंपनी लाभों में सुधार और विलयन तथा अधिग्रहण कार्यों में कुछ सुधार था।

भारत में एफडीआई का प्रवाह भी 2009 के दौरान कम हो गया किंतु अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न यह प्रवाह 2010 के दौरान भी कम बना रहा जबकि वैश्विक सुधार से पहले ही यहां मजबूत देशी वृद्धि हुई थी। इससे चालू खाते के घाटे के विस्तार की पृष्ठभूमि में भारत में नीति निर्माताओं की चिंता में वृद्धि हुई।

2010 के दौरान एफडीआई प्रवाहों की प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और मैक्सिको में 2009 की तुलना में 2010 में 14-171 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि हुई (सारणी 6)। इसके विपरीत भारत को एफडीआई के प्रवाह में 2010 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 32 प्रतिशत की गिरावट हुई। एफडीआई प्रवाहों में हुई इस गिरावट के कारण देश-वार दृष्टिकोण से इसके कारणों की गहन जांच आवश्यक हो गई है।

चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख समष्टिआर्थिक संकेतकों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत

## सारणी 6: चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई अंतर्वाह

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

	अर्जेंटीना	ब्राजील	चिली	भारत	इंडोनेशिया	मेक्सिको	दक्षिण अफ्रीका	थाईलैंड
2007	6.5	34.6	12.5	25.5	6.9	29.1	5.7	11.3
2008	9.7	45.1	15.2	43.4	9.3	24.9	9.6	8.5
	(50.2)	(30.3)	(21.1)	(70.3)	(34.5)	-(14.3)	(68.1)	-(24.7)
2009	4.0	25.9	12.7	35.6	4.9	14.5	5.4	5.0
	-(92.0)	-(14.3)	-(39.9)	-(49.4)	-(85.9)	-(200.8)	-(92.1)	-(120.2)
ति1-10	1.9	5.5	5.5	6.1	2.9	4.8	0.4	1.5
ति2-10	0.0	6.6	2.5	6.0	3.3	7.6	0.4	2.0
ति3-10	1.9	10.5	5.3	6.7	3.4	2.4	0.1	1.5
ति4-10	0.9	25.9	1.9	5.3	3.7	2.8	-	0.7
2010	4.7	48.5	15.2	24.1	13.3	17.6	0.9	5.7
	(17.5)	(87.3)	(19.7)	-(32.3)	(171.4)	(21.4)	-(80.4)	(14.0)

**टिप्पणी:** कोष्ठकों के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर हैं।

**स्रोत:** आईएमएफ, बीओपी सांख्यिकी।

का समष्टिआर्थिक निष्पादन अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, जिन्हें 2010 के दौरान काफी एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ था, जैसा ही रहा (चार्ट 1 और 2)।

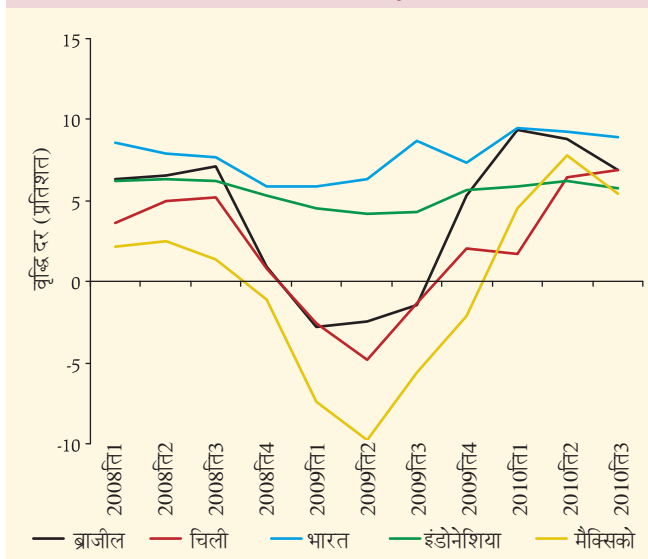
उदाहरण के लिए, 2010 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि में सुधार हुआ जैसा कि चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी हुआ था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाते के शेष में अर्जेंटीना को छोड़कर चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट हुई। किंतु भारत में मुद्रास्फीति अर्जेंटीना को छोड़कर चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सामान्यतः अधिक थी (काफी अवधि तक उच्च अर्थात् दो अंकीय बनी रही)।

इस प्रकार, 2010 के दौरान भारतीय समष्टिआर्थिक निष्पादन, जो कि चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसा ही था, में कोई विशेष गिरावट हुए बिना भारत के एफडीआई अंतर्वाहों में कमी आना उस संस्थागत कारक की संभाव्य भूमिका की ओर संकेत करता है जिसने एफडीआई अंतर्वाहों को हतोत्साहित किया होगा।

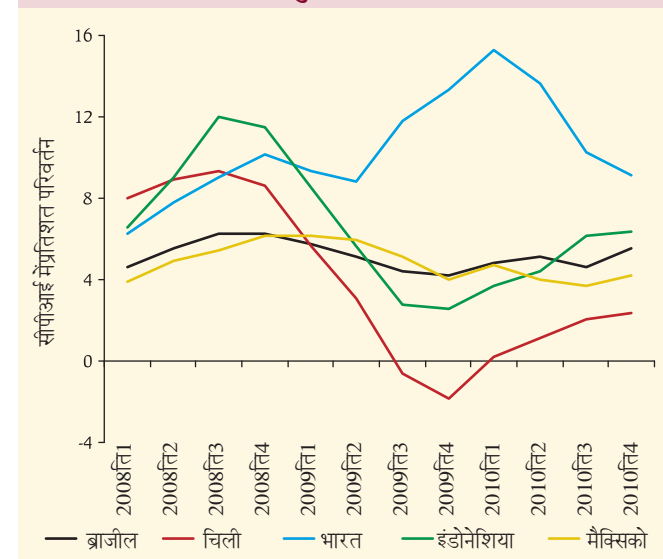
### 3.1 एफडीआई में नरमी - प्रस्तावित स्पष्टीकरण

हाल के समय में, विभिन्न अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कंपनी अनुसंधानकर्ताओं ने सुझाव दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण संबंधी क्रियाविधिक विलंब, जटिल नियमों और विनियमों के संदर्भ में भारत की विनियामक नीतियों, विधिक अपेक्षाओं और

चार्ट 1: जीडीपी वृद्धि



चार्ट 2: मुद्रास्फीति की दर



वातावरणीय बाध्यताओं ने निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोका होगा। नीति निर्माताओं द्वारा उठाए गए कदमों से उत्पन्न अनिश्चितताओं से भारत में कारोबारी वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। इस संदर्भ में विभिन्न रिपोर्टों में किए गए वक्तव्यों और टिप्पणियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सरकारी नियमों का अनुपालन करने, पर्यावरण के मानदंड और कानूनी अपेक्षाओं से जुड़े जोखिमों; अपर्याप्त यूजर शुल्क और कार्यपालन तथा निर्माण जोखिमों का सामना करना पड़ता है (क्रिसिल रिपोर्ट, जनवरी 2011)।

क्रियाविधिक विलंब लगभग सभी उत्तरदाताओं को परेशान कर रहा है जिसमें लगभग 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। प्रणाली और अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि काफी समय लगने वाली है और अनेक स्तरों के उच्चाधिकारियों से निपटना पड़ता है और अनेक निकायों से क्लियरेंस प्राप्त करना पड़ता है जिससे संबंधित प्रक्रियागत लागत काफी बढ़ जाती है और इसमें काफी प्रबंधकीय समय नष्ट हो जाता है जिससे निवेशकों के लिए यह मुद्दा काफी गंभीर चिंता का विषय बन गया है (एफआईसीसीआई का एफडीआई सर्वेक्षण, दिसंबर 2010)।

"पर्यावरणीय क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास" को इस्पात उद्योग में बड़ी निवेश परियोजनाओं को विलंबित करने वाले प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है (कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्विटी रिसर्च, अक्टूबर 2010)।

दि पास्को प्रोजेक्ट (इस पर कार्य जारी है) में व्यापक मामले कवर किए गए हैं: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 52,000 करोड़ रुपये जिसे विदेश से भारी मात्रा में पूंजी समाहित कर सकने की भारत की क्षमता की जांच के रूप में देखा जाएगा। उसी राज्य में (ओडिशा) वेदांता की खनन परियोजना पर्यावरण के कारण रुक चुकी है (टेलिग्राफ समाचारपत्र का समाचार, 19 अक्टूबर 2010)।

आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण किंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी गई बड़ी परियोजनाओं के संबंध में कड़े निर्णय लेने ही होते हैं। हमें यह वास्तविकता स्वीकारनी ही होगी कि विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल होना ही चाहिए (ईपीडब्ल्यू, 16 अक्टूबर 2010)।

सैकड़ों औद्योगिक परियोजनाओं के अलावा उन्होंने (पर्यावरण मंत्री) मुंबई के वाणिज्यिक हब में दूसरे हवाई अड्डे का कार्य रोका हुआ है और दर्जनों सड़कों तथा बांध की परियोजनाएं क्लियरेंस की राह देख रही हैं (चाहना डेली, 6 नवंबर 2010)।

इन धारणाओं की सत्यता की जांच के लिए जिसके लिए यह देखना होगा कि भारत में अन्य देशों की तुलना में, तुलनात्मक

रूप से अधिक प्रतिबंधात्मक पर्यावरण नीति के कारण एफडीआई प्रवाह कम हो गए होंगे, निम्नलिखित खंडों में चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों की सहायता से अर्थशास्त्रीय अध्ययन किया गया है।

### 3.2 एफडीआई में कमी आने के कारण - अर्थशास्त्रीय सबूत

सैद्धांतिक और चुनिंदा प्रायोगिक साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि एफडीआई प्रवाह पुल और पुश दोनों कारकों से प्रेरित थे। जहां समष्टिआर्थिक मानदंड दर्शाने वाले पुल कारक, मेजबान देश द्वारा अपनायी गई नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं, वहीं पुश कारक अनिवार्यतः वैश्विक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं और इन प्रवाहों को प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के नियंत्रण से बाहर रहते हैं (बाक्स I)

#### आंकड़े और कार्यप्रणाली

इस पेपर में एफडीआई प्रवाहों में बाधा बनने वाले कारकों का पता लगाने के लिए चुनिंदा बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए पैनल एक्सरसाइज का प्रयास किया गया है। डाटा सेट में 10 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं अर्थात् अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, भारत, मलेशिया, मेक्सिको, फिलीपीन्स, रूस, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड संबंधी 2003-04 से 2009-10 की स्थिति शामिल है। तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण डाटासेट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनान्स से लिया गया है। एफडीआई प्रवाहों को जीडीपी अनुपात की तुलना में एफडीआई अंतर्वाहों के रूप में लिया गया है जो स्पष्टीकरणात्मक परिवर्ती वस्तुओं के दायरे में पीछे आए हैं। ऊपर प्रस्तुत साहित्य समीक्षा से चुने गए और जो एफडीआई प्रवाहों के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, में आगे की मंदां शामिल हैं: बाजार का आकार, खुलापन, मुद्रा का मूल्यन, वृद्धि की संभावना, समष्टिआर्थिक सक्षमता, नियमित व्यवस्था और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त वैश्विक एफडीआई का अनुपात।

**बाजार का आकार :** बड़े बाजार द्वारा अधिक एफडीआई आकर्षित करने की संभावना होती है क्योंकि इनमें मांग के लिए अधिक संभावना की और बड़े पैमाने के कार्य से होने वाली लागत में कमी उपलब्ध होती है। बाजार का आकार क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में जीडीपी का प्रतिरूप होता है।

**खुलापन :** खुलेपन या उदारीकृत व्यापार का प्रभाव कुछ अस्पष्ट होता है और दो प्रभावों की तुलनात्मक शक्ति पर निर्भर करता है। पहला, व्यापार नियंत्रण से युक्त अर्थव्यवस्था से अधिक



### बॉक्स I विदेशी निवेश प्रवाह - सैद्धांतिक समर्थन

इस विषय पर अनुसंधान मुख्यतः उन कारकों पर केंद्रित किया गया है जो उन कारकों के प्रतिसाद में नीति निर्माण और एफडीआई को निर्धारित करते हैं। 1960 के दशक तक एफडीआई को नव-श्रेणीवाद पूंजी सिद्धांत के भाग के रूप में देखा गया था और मेजबान देश में इस पूंजी मूमेंट के पीछे का मूल उद्देश्य प्रतिफल की उच्च दर की खोज था। समयोपरांत यह बात समझ में आने पर कि पूंजी मूमेंट का उद्देश्य उच्च प्रतिफल की खोज से बहुत अधिक था, इस संबंध में बहुत से सैद्धांतिक और प्रायोगिक अनुसंधान हुए हैं जो पूंजी प्रवाहों के विविध प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारकों की पहचान करने पर केन्द्रित थे। यह हाइमर (1960) का विचार था जिन्होंने प्रत्यक्ष निवेश को संविभागीय निवेश से अलग करते हुए एफडीआई प्रवाहों के निर्धारक कारकों के अध्ययन का आधार निर्मित किया। हाइमर ने कुछ तथ्यों और साक्ष्यों<sup>2</sup> को रेखांकित किया जिनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष और संविभागीय निवेश के स्वरूप में भिन्नता होती है जिसके कारण इन दोनों प्रकार के निवेशों पर एक ही सिद्धांत लागू नहीं होगा। एफडीआई के प्रेरक के रूप में हाइमर द्वारा पहचाना गया मुख्य लक्षण नियंत्रण का स्तर था जिसे स्व-देश की संस्था मेजबान देश में प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से प्राप्त करती है। उन्होंने प्रतिस्पर्धी को अज्ञात ज्ञान के स्वामित्व, विदेश में निवेश करने वाली फर्म को लाभ देने वाले विभेदीकृत उत्पादों के अस्तित्व, उत्पाद की लाइसेंसिकरण संबंधी समस्याओं आदि जैसी बाजार की कमियों पर ध्यान केंद्रित किया जिनसे एफडीआई निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तथापि, साहित्य के अनुसार उनके सिद्धांत में संरचनात्मक बाजार की विफलता की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया है और बाजार की विफलता के लेनदेन लागत पक्ष की अनदेखी की गयी है (डनिंग 1981, रुमैन, 1980)। इसकी अलावा, उनके सिद्धांत में एफडीआई के स्थानगत और गत्यात्मक पहलू को स्पष्ट नहीं किया गया है।

बाद में, केव्ज (1071) ने प्रत्यक्ष निवेश के हाइमर के सिद्धांत को विस्तार प्रदान किया और इसे औद्योगिक संगठनात्मक साहित्य में शामिल किया। समतल और ऊर्ध्व एफडीआई में विभेद करते हुए उन्होंने निम्नलिखित कारकों की जानकारी प्राप्त की जैसे-उच्च कोटि के ज्ञान या जानकारी की प्राप्ति, कुछ आपूर्तिकर्ताओं की विशेषता वाले बाजार में अनिश्चितता से बचने का उद्देश्य और एफडीआई प्रवाहों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार के रूप में प्रवेश संबंधी प्रतिबंध का उद्देश्य। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय उद्यमों की बढ़ती उपस्थिति के कारण एफडीआई संबंधी दृष्टिकोण का

एफडीआई संबंधी अंतरराष्ट्रीयकरण सिद्धांतों, जिनमें लेनदेन लागत पर बल दिया गया, के साथ विस्तार किया गया। एफडीआई संबंधी अंतरराष्ट्रीयकरण सिद्धांतों में ज्ञान का संचय और अंतरराष्ट्रीयकरण को एफडीआई के लिए प्रेरक माना गया है, जो ज्ञान के मध्यस्थ उत्पाद बाजारों के संबंध में आसान मार्ग है।

होस्ट (1972) जैसे विचारकों, जिन्होंने एफडीआई के स्थानगत निर्बंधों पर बल दिया, ने एफडीआई प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में नैसर्गिक संसाधनों की उपस्थिति की पहचान की। व्हीलर और मोदी (1992) ने इरगोडिक और नॉन-इरगोडिक प्रणालियों की पहचान की जो एफडीआई के स्थान का निर्धारण करती हैं। इरगोडिक प्रणाली में भौगोलिक विशेषताओं, श्रम लागत, परिवहन लागत और बाजार के आकार जैसे श्रेणीबद्ध बदलते घटकों पर एफडीआई प्रवाहों के निर्धारक कारकों के रूप में बल दिया गया है। विभिन्न प्रायोगिक अध्ययन अब भी एफडीआई प्रवाहों की संभावना के निर्धारण के लिए इन बदलते घटकों पर निर्भर हैं। नॉन-इरगोडिक प्रणाली में उन बाह्यताओं पर बल दिया गया है जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की फर्मों में निवेश से उभरती हैं, दूसरे शब्दों में एफडीआई का समूहगत प्रभाव दर्शाती हैं।

डनिंग के अनुसंधान कार्य (1977, 1981) में एफडीआई का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है जो स्वामित्व, स्थान और अंतरराष्ट्रीयकरण के उदाहरण पर आधारित है। एफडीआई के उनके ग्रहणशील (एकलेक्टिक) सिद्धांत में एफडीआई से उभरने वाले विभिन्न लाभों को रेखांकित किया गया है: स्वामित्व-विशेष का लाभ जिसमें अतिरिक्त क्षमता तक पहुंच, संयुक्त आपूर्ति की बचत, बाजार और ज्ञान तक अधिक पहुंच, जोखिम का बंटवारा, प्रौद्योगिकी और ट्रेडमार्क, फर्म का आकार; स्थान-विशेष संबंधी लाभ जिसमें निविष्टियों का वितरण और बाजार, श्रम लागत, सामग्री और परिवहन लागत, सरकारी हस्तक्षेप और नीतियां, वाणिज्यिक और विधिक मूलभूत सुविधाएं आदि शामिल हैं; अंतरराष्ट्रीयकरण-विशेष लाभों के अनुसंधान में कटौती, वार्ता और निगरानी लागत, प्रशुल्क से बचना आदि शामिल है। एफडीआई के ग्रहणशील सिद्धांत के आलोचकों ने इसे एफडीआई के सिद्धांत के बजाय कर-अर्थव्यवस्था से संबंधित माना है क्योंकि इसमें अनेक सिद्धांत और परिवर्ती घटक शामिल हैं। एफडीआई की समकालीन प्रवृत्ति दशानि और नए विचारों को शामिल करने हेतु इसे पुनः संरचित करने के लिए भी इसकी आलोचना हुई है। उनके सिद्धांतों में प्राथमिक रूप से एफडीआई प्रवाहों के निर्धारण में रणनीति की भूमिका की अनदेखी की गई है। रणनीतिक उद्देश्यों की भूमिका, जिसका पहली बार विश्लेषण किनकरबोकर द्वारा किया गया था (1973), को अकोसिला द्वारा आगे बढ़ाया गया (1991)। इन रणनीतिक सिद्धांतों के अनुसार,

<sup>2</sup> हाइमर ने ऐसे प्रमाण दिए जैसे निवल निर्यातक लेकिन पोर्टफोलियो निवेश के निवल आयातक के रूप में अमरीका का मामला, विनिर्माण में प्रत्यक्ष निवेश तथा वित्तीय संगठनों के पोर्टफोलियो निवेश की प्राधान्यता तथा विभिन्न देशों में निवेश का वैभिन्नीकरण करके जोखिम को कम करने के लिए उपलब्ध अवसरों के बावजूद किसी एक देश में निवेश।

## बॉक्स I विदेशी निवेश प्रवाह - सैद्धांतिक समर्थन (समाप्त)

रणनीतिक गठबंधनों, के पीछे के कारणों में बड़े पैमाने के लाभ, जोखिम में कमी और ज्ञान तथा विशेषज्ञता तक पहुंच शामिल है। रणनीतिक गठबंधन, विलयन और अधिग्रहण में तेजी के इस युग में हो रहे विलयन और अधिग्रहण के उद्देश्यों को रेखांकित करते हैं।

ये सभी सिद्धांत मुख्यतः एफडीआई के आपूर्ति पक्ष को स्पष्ट करते हैं जो कि एफडीआई को गृह अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाते हैं। मोटे तौर पर, इन कारकों और उद्देश्यों में ज्ञान का लाभ, कम लागत का लाभ, अधिक बाजार पहुंच, बड़े पैमाने से संबंधित लाभ के माध्यम से लाभ-वृद्धि और निविष्टि आपूर्तियों की प्राप्ति या लगभग एकाधिकार जैसी विश्वव्यापी शक्ति का निर्माण, स्थानगत लाभ, जोखिम में कमी और संचयी लाभ जैसे रणनीतिक उद्देश्य शामिल हैं।

मांग पक्ष के उन कारकों पर भी बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है जो किसी मेजबान अर्थव्यवस्था में एफडीआई को आकर्षित करते हैं। विश्व बैंक (1995), ब्लामस्ट्रॉम और कोको (2001) जैसे अध्ययनों में मेजबान देश के लिए एफडीआई से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला गया है जो प्रतिस्पर्धा और दक्षता प्रभाव, स्पिल ओवर प्रभाव, पश्चगामी और अग्रगामी संबद्धताओं, प्रौद्योगिकी प्रभाव, ज्ञान पूंजी के संग्रहण, बिना ब्याज चुकौती दायित्वों के निधियों के स्थिर प्रवाह, समष्टिआर्थिक नीति पर व्यापक बाह्य बाजार अनुशासन, राष्ट्रीय पूंजी बाजार को व्यापक और गहन बनाने आदि के रूप में हैं। इन सैद्धांतिक अध्ययनों ने एफडीआई के अंतर्वाह और बहिर्वाह को निर्धारित करने वाले कारकों तथा एफडीआई आकर्षित करने के लिए मेजबान देशों की ओर से किये गये नीतिगत उपायों की भूमिका पर आनुभविक अनुसंधान को काफी अधिक स्थान दिया है। इन देश विशिष्ट अध्ययनों में एफडीआई आकर्षित करने में मेजबान देश की नियामक व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। इन अध्ययनों में समय, पर्यवेक्षी अधिकारियों की गतिविधियों तथा बाह्य और आंतरिक विनियामी उपायों की विषय-वस्तु पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

नीतिगत वातावरण की भूमिका पर प्रकाश डालने वाले काफी बड़े साहित्य में एफडीआई के लिए निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के मुद्दे पर चर्चा की गयी है। ऑक्सेलहीम (1993) के अनुसार, राष्ट्रीय बाजार से वैश्विक बाजार के एक अंतर्संबद्ध हिस्से में, संक्रमण की अवधि के दौरान आवक निवेश आकर्षित करने में, सरकारें इंटरवेशन का काफी अधिक समिश्र प्रयोग करके पूंजी की सापेक्षिक लागत को प्रभावित कर सकती हैं। नीति निर्माता, कंपनी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं वे ऐसा अंतरराष्ट्रीय सापेक्षिक मूल्यों, विनिमय दरों, सापेक्षिक मुद्रास्फीति और ब्याज दरों का प्रबंधन करके उत्पादन सुविधाओं के स्थान का पता लगाकर कर सकती हैं। सामान्य रूप में, वे अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति समता और अंतरराष्ट्रीय फिशर इफेक्ट से अलगव तय करके, निवेश प्रोत्साहन अथवा कारोबारी अवसर पैदा कर सकते हैं। नीति-निर्माताओं द्वारा नियंत्रित अतिरिक्त कारोबारी प्रोत्साहन सापेक्षिक कर और सापेक्षिक राजनैतिक जोखिम हैं। इस अध्ययन में तर्क दिया गया है कि एफडीआई आकर्षित करने के लिए समुचित नीतियां एक आवश्यक शर्त प्रतीत होती हैं।

दि युनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन ने एफडीआई आकर्षित करने के लिए सात नीति लिखत उपलब्ध कराए हैं: स्वामित्व नीति, कर और सब्सिडी उपाय, विदेशी मुद्रा की परिवर्तनीयता और अनर्जनों के प्रेषणों से संबंधित नीति, मूल्य नियंत्रण उपाय, कार्यनिष्पादन अपेक्षा, सेक्टर - विशिष्ट सीमाएं तथा प्रोत्साहन और विविध एंटी एवं ऐसे प्रक्रियागत नियम जो संभावित एफडीआई पर काफी अधिक लागत लगाएंगे। एफडीआई विनियमन (2010) के संकेतकों पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक और पुराने नियम तथा विनियमन, एफडीआई को रोकते हैं, लालफीताशाही और कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन एफडीआई के लिए और बाधाएं खड़ी करता है, अच्छे विनियमों और कुशल प्रक्रियाओं से एफडीआई को लाभ पहुंचता है तथा प्रभावी संस्थाओं से एफडीआई को पोषित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार, इस रिपोर्ट में विनियामी ढांचे के महत्त्व पर जोर दिया गया है।

समतल एफडीआई आकर्षित होने की संभावना है ताकि उत्पादन-स्थलों का निर्माण उन नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर हो सके। दूसरा, बढ़ते खुलेपन से सस्ते मध्यस्थ और पूंजीगत माल की खोज में ऊर्ध्व एफडीआई प्रवाह आकर्षित होते हैं (रेश्मनी, 2000)। साथ ही, व्यापार में खुलापन ऐसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक उदारीपन से संबंधित होता है जो निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है। खुलापन जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू प्राप्तियों और भुगतान के योग के रूप में दिखता है।

*समष्टिआर्थिक स्थिरता* - कम मुद्रास्फीति दर और स्थिर विनिमय दर अनिश्चित जोखिम को कम करेगी तथा और अधिक एफडीआई को आकर्षित करेगी। इसे मुद्रास्फीति और विनिमय दर उतार-चढ़ाव में देखा जा सकता है।

*विनिमय दर मूल्यन* - फ्रूट और स्टीन (1991) ने साफ तौर पर पाया है कि एक कमजोर मेजबान देश की मुद्रा में आवक एफडीआई को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि मूल्यहास मेजबान

देश की आस्तियों को अपने देश की आस्तियों की तुलना में कम व्ययसाध्य बनाता है जिससे यह शीर्ष एफडीआई को आकर्षित कर सकता है। दूसरी तरफ, एक मजबूत वास्तविक विनिमय दर घरेलू तौर पर उत्पादन करने के लिए विदेशी कंपनियों के प्रोत्साहन को सुदृढ़ बनायगी जिससे और अधिक समतल एफडीआई को आकर्षित किया जा सकेगा। लेकिन, दूसरे मत को आनुभविक साहित्य (वालश और यू, 2010) में बहुत अधिक समर्थन नहीं मिलता लग रहा है। इसको संबंधित देश की मुद्रा के अर्थ में अमरीकी डॉलर के मूल्य में मापा गया है।

**समूहन प्रभाव:** एफडीआई के बड़े स्टॉक को विदेशी निवेशकों के लिए एक सौम्य कारोबार परिवेश के एक संकेतक के रूप में माना जाता है तथा इस प्रकार और अधिक एफडीआई आकर्षित होती है। अन्य फर्मों के साथ समूहन करने से, नये निवेशकों को मेजबान देश के मौजूदा निवेशकों से धनात्मक स्पिलओवर का लाभ होता है। व्हीलर और मोदी (1992), बैरल और पैन (1999) तथा कैम्पोस और किनोशिदा (2003) के अध्ययनों में समूहन प्रभावों के आनुभविक साक्ष्य पाये गये हैं। इसको एफडीआई के स्टॉक के रूप में वर्णित किया गया है।

**संस्थाएं और गवर्नेंस** - संस्थागत और गवर्नेंस गुणवत्ता की एफडीआई के एक संभावित निर्धारक के रूप में पहचान की गयी है, अनेक कारणों से विशेष रूप से कम विकसित देशों के लिए। दो, वे कमजोर संस्थाएं जो भ्रष्टाचार बढ़ाती हैं, निवेश लागत को बढ़ाएंगी और लाभ को कम करेंगी। तीन, एफडीआई की ऊंची डूबंत लागत निवेशकों को अनिश्चितता के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील बनाएगी, राजनैतिक अनिश्चितता और कमजोर संस्थाओं से होने वाली अनिश्चितता सहित (वालश और यू, 2010)। संस्थागत ढांचे और गवर्नेंस को 'सरकारी प्रभावकारिता' संकेतक (कॉफमान संकेतक)<sup>3</sup> में शामिल किया गया है। इसमें *सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता, लोक सेवा की गुणवत्ता, और राजनैतिक दबावों से इसकी स्वतंत्रता की मात्रा, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता और ऐसी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता की धारणाओं को शामिल किया गया है।* -2.5 से 2.5 तक के पैमाने को स्कोर दिया गया है। इसमें अधिक स्कोर का तात्पर्य है सरकारी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम है।

**समष्टि आर्थिक संपुष्टता** विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की एक प्रमुख कारक हो सकती है। यदि सरकारी वित्त और बाह्य क्षेत्र को संवहनीय संपुष्ट माना जाता है तो विदेशी निवेशक

अपने निवेश की सुरक्षा के बारे में आश्वास्त महसूस करते हैं। इस संपुष्टता को दो परिवर्तनशील चरों के माध्यम से पाया जा सकता है। राजकोषीय संपुष्टता को जीडीपी की तुलना में जीएफडी अनुपात में पाया गया है और बाह्य क्षेत्र की संपुष्टता को जीडीपी की तुलना में निवल आईआईपी में पाया गया है।

आकर्षित करने वाले इन कारकों के अलावा, वैश्विक आर्थिक परिवेश और विकसित विश्व के नीतिगत रुझान जैसे विकर्षित करने वाले कारक एफडीआई प्रवाह को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक चलनिधि की अधिकता, उच्चतर प्रतिफल की खोज करने वाली उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए और अधिक संसाधनों के प्रवाह का कारण बनेगी।

### आंकड़ों की सीमाएं

अध्ययन में निकाले गये निष्कर्षों को आंकड़ों की निम्नलिखित सीमाओं के आलोक में देखा जाना चाहिए:

- यह अध्ययन मैक्रो स्तर के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें एफडीआई के निर्धारण में फर्म विशिष्ट विशेषताओं को संरक्षी से नहीं लिया गया है।
- तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवर्ती चर के आंकड़ों को एक एकल स्रोत से लिया गया है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां तुलनीयता के लिए उपयुक्त समायोजन कर सकती हैं, एक वैयक्तिक देश के आंकड़े अपने देश के आंकड़ों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
- जैसा कि कृषि, बैंकिंग, मीडिया, 'निर्माण, पर्यटन और एकल ब्रांड खुदरा' के संबंध में विश्व बैंक ने अपने सर्वेक्षण 'विदेश में निवेश' में कहा है भारत के लिए सैक्टरोल सीमा विद्यमान दिशा-निर्देशों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। यह इस कारण से है क्योंकि औसत सीमाओं को इसके प्रकाशनों के संबंधित खंडों में रिपोर्ट किया जाता है और उसे अध्ययन में शामिल किया गया है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के किसी समूह के लिए निम्नलिखित स्वरूप में निश्चित प्रभाव मॉडल<sup>4</sup> का अनुमान लगाया गया जिसमें  $t$  वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था का जीडीपी की तुलना में एफडीआई अनुपात  $fy(i,t)$  है और  $x(i,t)$  व्याख्यात्मक परिवर्ती चरों का वाहक है।

<sup>3</sup> इसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के डी कॉफमान और विश्व बैंक के ए क्राय एंड एम. मस्टर्ज्जी के द्वारा तैयार "वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स" के भाग के रूप में तैयार किया गया।

<sup>4</sup> चूंकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच कुछ विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं, जिन्हें भारत को स्पर्धा देने के लिए माना जाता है, को नमूने में शामिल किया गया है, इसे औचक नमूनीकरण नहीं माना जा सकता है।

$$y(i,t) = a_1 d_1(i,t) + a_2 d_2(i,t) + \dots + b_{qx}(i,t) + e(i,t) \\ = a(i) + b_{qx}(i,t) + e(i,t),$$

जहां  $a(i)$  वैयक्तिक विशिष्ट स्थिरांक है, और  $d(i)$  को समूह विशिष्ट नमूना परिवर्ती चर माना जाता है जो केवल समान 1 तभी होते हैं जब  $j=i$  होता है।

10 देशों<sup>5</sup> के लिए 2000-01 से 2010-11 तक की अवधि के लिए पैनेल के लिए अनुमान लगाया गया है।

### परिणाम

अनुमानित समीकरण<sup>6</sup> नीचे दर्शाया गया है जबकि  $t$  सांख्यिकी को कोष्ठक में दर्शाया गया है:

$$Fy = -1.42 + 0.03 \text{ openness} - 0.004 \text{ dwages} + 0.009 \text{ FDIEMERG} + \\ (2.6) \quad (6.1) \quad (2.3) \quad (3.5)$$

$$.08 \text{ Gdiff} + 4.08 \text{ Govt. Effect} (-2) + 0.02 \text{ IIPY} (-1) \\ (2.6) \quad (4.1) \quad (2.4)$$

$$R^2 = .75, D.W. = 2.04$$

जहाँ

$f_y$ - जीडीपी की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुपात;  $\text{Openness}$  - जीडीपी की तुलना में चालू प्रवाह अनुपात;  $\text{Gdiff}$  - नमूना देशों के बीच वृद्धि अंतर;  $\text{dwages}$  - श्रम लागत में परिवर्तन;  $\text{FDIEMERG}$ = उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई का आकार;  $\text{IIPY}$  - निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति;  $\text{Govt. effect}$ -सरकारी प्रभावकारिता का सूचकांक (कॉफमान सूचकांक)।

पूर्व अपेक्षाओं के अनुसार, सभी पुल करने वाले कारक जैसे खुलापन, वृद्धि अंतर, निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति और सरकारी प्रभावकारिता का कॉफमान सूचकांक सकारात्मक रूप से संबद्ध पाया गया। अपेक्षा के अनुसार, श्रम लागत के एफडीआई अंतर्वाहों के साथ प्रतिकूल संबंध थे। सभी परिवर्ती चर सांख्यिकी तौर पर काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाहित हो रही एफडीआई के आकार के माध्यम से आये पुश कारक भी धनात्मक रूप से संबद्ध पाए गए और इसका प्रभाव सांख्यिकी तौर पर काफी अधिक रहा है।

<sup>5</sup> पैनेल असंतुलित है क्योंकि सभी देशों के लिए श्रम लागत के आंकड़े 2008-09 से पहले के उपलब्ध नहीं थे। लेकिन, 2000-01 से 2008-09 तक के लिए अनुमानित संतुलित पैनेल के परिणाम, पूर्ण अवधि के पैनेल के परिणामों से बहुत अधिक अलग नहीं थे और ये अनुमान किसी भी रूप में भिन्न नहीं थे।

<sup>6</sup> वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जोरिखिम से बचाव को हिसाब में लेने के लिए 2009/2010 की डमी को शामिल किया गया है। इसके अलावा, 2004-05 की अवधि के लिए भारत विशिष्ट डमी का भी प्रयोग किया गया है।

बाजार के आकार को समाहित करने वाले, पीपीपी के अर्थ में, जीडीपी की भी जांच की गयी। यद्यपि यह सांख्यिकी तौर पर काफी अधिक रही (जानकारी नहीं दी गयी), इसके संकेत पूर्व अपेक्षाओं के अनुरूप थे अर्थात् जितना बड़ा बाजार होगा उतनी ही अधिक एफडीआई होगी। इसी प्रकार, विनिमय दर के संकेत, यद्यपि पूर्व अपेक्षा के अनुसार सही थे, सांख्यिकी तौर पर नगण्य थे और उनकी जानकारी नहीं दी गयी है।

परिणाम दर्शाते हैं कि खुलेपन, वृद्धि अंतर तथा आईआईपी में दस प्रतिशत अंकों की वृद्धि से जीडीपी की तुलना में एफडीआई अनुपात में क्रमशः 0.3, 0.8 और 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक एफडीआई के आकार में प्रत्येक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि से एफडीआई / जीडीपी अनुपात में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, मजदूरी दर में प्रत्येक 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि से एफडीआई अनुपात में .04 प्रतिशत अंक की कमी होने की संभावना है।

सूचकांक दर्शाने वाले 'सरकारी प्रभावकारिता', जैसाकि आशा है, का एफडीआई प्रवाह के साथ प्रतिकूल संबंध है, इसका तात्पर्य है कि नीतिगत निश्चितता एफडीआई अंतर्वाहों की प्रमुख निर्धारक हो सकती है। हमारे परिणामों के अनुसार यदि -2.5 से 2.5 तक के पैमाने पर सरकारी प्रभाव सूचकांक एक अंक तक बढ़ता है तो जीडीपी की तुलना में एफडीआई अनुपात 4 प्रतिशत अंक बढ़ जाता है।

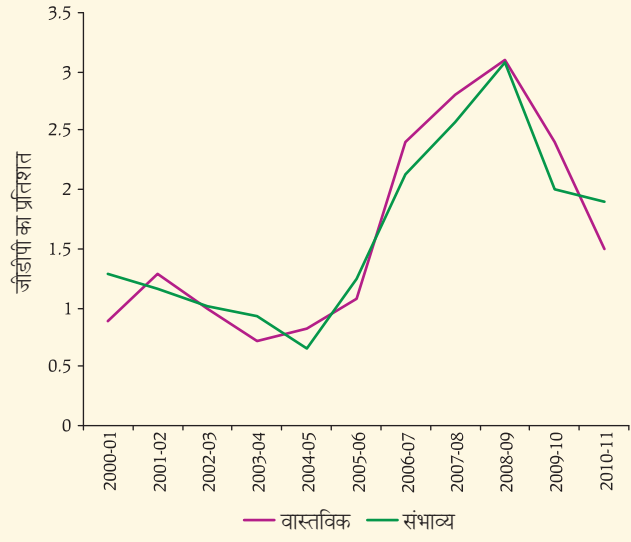
इस प्रकार, पैनेल के परिणाम दर्शाते हैं कि जितनी अधिक खुलेपन की मात्रा होगी, अर्थव्यवस्था की प्रत्याशित वृद्धि होगी, अंतरराष्ट्रीय उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर निवल अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और एफडीआई का आकार होगा, उस देश में प्रवाहित होने वाले एफडीआई का आकार उतना ही बड़ा होगा। इसी प्रकार, कुशल और गुणवत्तापूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन की सुनिश्चितता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक एफडीआई का प्रवाह होगा। दूसरी तरफ, अधिक श्रम लागत से देश के लिए एफडीआई के प्रवाह के हतोत्साहित होने की संभावना है।

### 2010-11 के दौरान किस कारण से भारत में एफडीआई के प्रवाह में गिरावट आई?

हमारे आनुभविक अभ्यास से कई ऐसे कारकों का पता चला है जो एफडीआई प्रवाह के आकार को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सरकारी नीति सहित आर्थिक से इतर कारकों को विलग करने के लिए, कॉफमान सूचकांक को छोड़कर सभी व्याख्यात्मक परिवर्ती चरों के मूल्यों को अद्यतन करके वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक स्थिति से भिन्न एक परिदृश्य तैयार किया गया। अनुमानित संभावना और वास्तविक एफडीआई को चार्ट 3 में दिया गया है तथा



चार्ट 3: एफडीआई अंतर्वाह - वास्तविक और संभाव्य

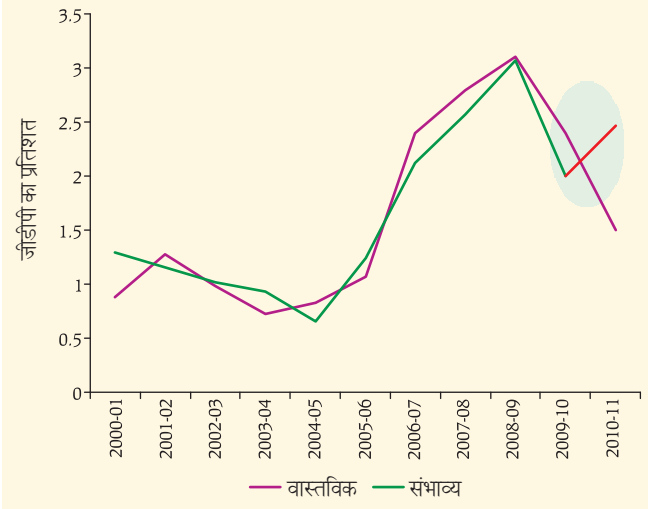


वास्तविक स्थिति से भिन्न परिदृश्य, जिसमें सरकारी प्रभावकारिता सूचकांक में किसी गिरावट को शामिल नहीं किया गया है, चार्ट 3 क में दिया गया है।

चार्ट 3 से पता चलता है कि भारत की ओर वास्तविक एफडीआई, संभावित एफडीआई के मार्ग पर आगे बढ़ी। संभावित एफडीआई स्तर वह स्तर होता है जो अंतर्निहित मूल तत्वों के रुझानों को देखते हुए घटित होता है। वर्ष 2010-11 में, जीडीपी के 1.5 प्रतिशत का वास्तविक एफडीआई प्रवाह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के अनुमानित स्तर से मामूली रूप से कम था। चार्ट 3 क में वास्तविक स्थिति से भिन्न एक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है जहां वर्ष 2010-11 के लिए 'सरकारी प्रभाव' को छोड़कर सभी परिवर्ती चरों के मूल्यों को अद्यतन करके एफडीआई प्रवाह के संभावित स्तर का पता लगाया गया है। बाद वाले को पूर्व वर्ष के स्तर पर रखा गया है। वर्ष 2010-11 में वास्तविक स्थिति से भिन्न परिदृश्य के मामले में पता चलता है कि एफडीआई के संभावित और वास्तविक स्तर के बीच अंतराल में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। चूंकि 2010-11 के लिए अनुमानित वास्तविक स्थिति से भिन्न परिदृश्य में, सरकारी प्रभाव को छोड़कर सभी अन्य परिवर्ती चरों के मूल्य को अद्यतन किया गया है, वर्ष के दौरान संभावित और वास्तविक के बीच काफी अधिक अंतराल के लिए सरकारी प्रभावकारिता<sup>7</sup> सूचकांक को उत्तरदायी माना जा सकता है।

<sup>7</sup> एफडीआई के विभिन्न प्रेरकों को निर्धारित करते समय, एफडीआई के मूल्य के अलावा, एफडीआई प्रस्तावों की संख्या के अर्थ में भी प्रभाव की जांच की गई। यह पाया गया कि एफडीआई के मूल्य के अर्थ में अथवा प्रस्तावों की संख्या के अर्थ में निकाले गये परिणाम एक जैसे थे। यह देखा गया कि जब एफडीआई के मूल्य में गिरावट आती है, तो बड़े-बड़े आकार के निवेश प्रस्तावों की संख्या भी कम होती जाती है।

चार्ट 3 क: एफडीआई अंतर्वाह - वास्तविक और संभाव्य (स्थिर नीतिगत व्यवस्था मानते हुए)



दूसरे शब्दों में, वर्ष 2010-11 के लिए एफडीआई के वास्तविक स्थिति से भिन्न परिदृश्य में सभी आर्थिक परिवर्ती चरों को शामिल किया गया है अर्थात् वृद्धि अंतर, खुलापन, निवल आईआईपी, श्रम लागत, ऐसी सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई के आकार जहां पर 'सरकारी प्रभाव' को अपरिवर्तित रखकर गुणवत्तापूर्ण परिवर्तनशील चरों को रखा गया है। 'सरकारी प्रभाव' को अपरिवर्तित रखने का तात्पर्य होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में नीतिगत अनिश्चितता में कोई वृद्धि नहीं हुई। भारत में एफडीआई अंतर्वाह वास्तव में प्राप्त हुए की तुलना में, 35 प्रतिशत से अधिक होंगे।

इस प्रकार, आनुभविक परिणाम ऊपर प्रस्तुत विश्लेषण में किये गये हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कारक एफडीआई प्रवाहों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और समष्टिआर्थिक परिवर्ती चरों में किसी गिरावट के अभाव में एफडीआई प्रवाहों में कमी संभवतः ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण कारकों के कारण हो सकती है।

#### खंड 4: निष्कर्ष

वैश्विक और विभिन्न क्षेत्रों/देशों के स्तर पर एफडीआई प्रवाहों के हाल के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने सावधानीपूर्वक पूंजी खाता उदारीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में, सामान्य रूप से अपने सुदृढ़ घरेलू आर्थिक कार्यनिष्पादन और एफडीआई नीति के क्रमिक उदारीकरण के अनुरूप उच्चतर एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। हाल के वैश्विक संकट के दौरान भी, भारत के प्रति एफडीआई अंतर्वाह में उतनी कमी नहीं दिखी जितनी वैश्विक



और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में दिखी। 2010-11 के दौरान जब उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक एफडीआई प्रवाह की स्थिति में सुधार हुआ, वैश्विक रिकवरी के पहले सापेक्षिक रूप से बेहतर घरेलू आर्थिक कार्यनिष्पादन के बावजूद, भारत के प्रति एफडीआई प्रवाह की गति धीमी बनी रही। इससे प्रश्न खड़े हुए हैं विशेष रूप से चालू खाता घाटे के लगभग 3 प्रतिशत के धारणीय स्तर से अधिक होने की पृष्ठभूमि में।

ऐसी कमी के पीछे के कारकों का विश्लेषण करने के लिए एक आनुभविक अभ्यास किया गया जिसमें समष्टिआर्थिक परिवर्तनशील चरों के सुदृढ़ होने के बावजूद, भारत में एफडीआई अंतर्वाहों में गिरावट के मूल में संस्थागत कारकों (सरकार को गुणवत्ता नीति प्रशासन को लागू करना है) की भूमिका बतायी गई।

10 प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के एक पैनल अभ्यास में दर्शाया गया कि एफडीआई खुलेपन, वृद्धि संभावनाओं, समष्टि आर्थिक धारणीयता (अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति), श्रम लागत और सरकारी प्रभावकारिता से काफी अधिक प्रभावित है।

अंतर्निहित समष्टिआर्थिक मूल तत्वों के आधार पर निर्धारित संभावित स्तर के समकक्ष भारत के प्रति वास्तविक एफडीआई प्रवाह की एक तुलना में दर्शाया गया कि वास्तविक एफडीआई, जो सामान्य रूप से 2009-10 के संभावित स्तर पर थी, 2010-11 के दौरान लगभग 25 प्रतिशत के अपने संभावित स्तर से नीचे गिर गई। इसके अलावा, आर्थिक और आर्थिक से इतर कारकों को अलग-अलग करने के वास्तविक स्थिति से भिन्न परिदृश्य से ऐसा सुझाव मिलता प्रतीत हो रहा है कि 2010-11 के दौरान वास्तविक और संभावित के बीच व्यापक विषमता आंशिक तौर पर नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि के कारण थी।

संस्थागत कारकों की भूमिका के अलावा, अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, कृषि सहित ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं जहां पर एफडीआई को अनुमति नहीं है, जबकि बीमा और मीडिया जैसे कुछ क्षेत्रों में सेक्टरल सीमा वैश्विक पैटर्न की तुलना में सापेक्षिक रूप से कम है। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि ये सीमाएं और प्रतिबंध घरेलू विचार-विमर्श पर आधारित हैं और ऐसे कोई समान मानक नहीं हैं जो सभी देशों पर एक जैसे लागू हों। चूंकि अर्थव्यवस्था, आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है और यदि घरेलू आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो एफडीआई प्रवाहों (विशेष रूप से मल्टी-ब्रांड खुदरा में) पर सेक्टरल सीमा और प्रतिबंधों पर पुनर्विचार की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा,

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को देखते हुए यह तर्क किया जाता है कि खुदरा में एफडीआई से, संगठित आपूर्ति शृंखला के लाभों को उठाने और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को बेहतर मूल्य देकर बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी। भारत में मुख्य आशंका यह है कि खुदरा में एफडीआई से देशी खुदरा विक्रेताओं - विशेष रूप से छोटे परिवार द्वारा चलायी जाने वाली दुकानों को अनिश्चित स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप देशी खुदरा विक्रेताओं को बड़े पैमाने पर बाहर जाना होगा और इस प्रकार काफी अधिक नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ेगा। इस संबंध में एक संतुलित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस पीढ़ी में दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, आणविक शक्ति से पैदा की गई बिजली का पारेषण और संवितरण है, जहां पर वर्तमान में एफडीआई को अनुमति नहीं दी गई है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बिजली संवितरण सेवा एफडीआई का एक पसंदीदा क्षेत्र है। अंकटाड के अनुसार 2009 के दौरान सीमा पार किये गये सर्वोच्च दस में से चार सौदे इस खंड में थे जिससे समग्र एफडीआई में गिरावट को देखते हुए, इस क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि हुई। इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की वर्तमान एफडीआई सीमा को बढ़ाने की मांग की समीक्षा की जा सकती है जिसमें परिवर्तनशील जनांकिकीय पैटर्न और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक वित्त की अपेक्षा को पूरा करने में बीमा कंपनियों की भूमिका को ध्यान में रखना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, यह आवश्यक है कि भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाने के लिए 1 अप्रैल 2012 को भारत सरकार ने कई उपायों की घोषणा की। इन उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शामिल हैं (i) नकदेतर लेन-देनों पर इक्विटी शेयरों के निर्गमन की अनुमति देना जैसे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत पूंजी माल का निर्यात, (ii) 'एक ही क्षेत्र' में मौजूदा संयुक्त उद्यमों / तकनीकी सहयोग के मामले में पूर्व अनुमोदन की शर्त को हटाना, (iii) कनवर्जन फार्मूला निर्धारित करने के लिए कंपनियों को लोच प्रदान करना बशर्तकि फेमा / सेबी के दिशानिर्देश हों, परिवर्तनीय लिखतों के मूल्य का सीधा-सीधा उल्लेख न हो; (iv) कंपनियों के दो वर्गों - 'विदेशी निवेशकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली कंपनियां' और 'भारतीय निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियां' में वर्गीकरण के लिए कार्यविधि को सरल करना तथा (iv) बीजों के विकास और उत्पादन तथा 'नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत' बिना शर्त सामग्री प्लांट करने में एफडीआई को अनुमति देना। इन उपायों से आशा है कि भारत की छवि को एक पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा और निकट भविष्य में भारत में एफडीआई अंतर्वाह आकर्षित होंगे।

## चुनिन्दा संदर्भ

एकोसेला, एन.स्ट्रेटिजिक फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ईसी.,  
इकोनॉमिक नोट्स खंड 20, सं.2, 1991।

अहलूवालिया, एम.एस.(2011),“एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल इज गुड, बेनिफिट्स फारमर्स” दि टाइम्स ऑफ इंडिया ,  
<http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/FDI-in-multi-brand-retail-is-good-benefits-farmers-Montek-/articleshow/7328844.cms#ixzz1EmeD95sm>”.

अहन,चूंग यांग (2008), “न्यू डाइरेक्शंस ऑफ कोरियाज फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन दि मल्टी-ट्रेक एफटीए इरा : इन्ड्यूस्मेंट एंड आफ्टरकेयर सर्विसेज”, ओईसीडी ग्लोबल फोरम फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मार्च।

अली शौकत और वेई गुओ (2005), ‘डिटरमिनेंट्स ऑफ एफडीआई इन चाइना,’ जर्नल ऑफ ग्लोबल बिजनेस एंड टेकनॉलोजी, खंड 1, 2 नवंबर, फाल।

अन्नास, पोल, मिहिर ए, देसाई, एंड सी; फ्रिट्ज फोले (2007), ‘मल्टी नेशनल फर्म्स, एफडीआई फ्लोज एंड इंपरफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.12855 जनवरी।

ब्लोनाइजेन, ब्रूस ए, (2005), ए रिव्यू ऑफ दि इम्पयारिकल लिटररेचर ऑन एफडीआई एंड डिटर मिनेंट्स’ एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.11299, अप्रैल।

ब्रिम्बले, पीटर (2002), दि फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट : परफोरमेंस एंड अट्रैक्शन दि केस ऑफ थाइलैंड, 2002। वर्कशॉप ऑन फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट : अपोर्चुनिटीज एंड चेलेंजेस फॉर कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम इन हनोई, अगस्त।

केक्स, आर.ई.(1971) “इण्टरनेशनल कारपोरेशंस : दि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट,” इकोनॉमिका।

डनिंग, जन.एच (1977), “ट्रेड लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दि मंटी नेशनल इंटरप्राइज : ए सर्च फॉर एंड इक्लेक्टिक एप्रोच इन ओहलिन बी: जेसलबोर्न, पी ओ.; और विकमैन, पी.एम (संपा) दि इंटरनेशनल एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लंदन; मैकमिलन।

----- (1981) “एक्सप्लेनिंग दि इंटरनेशनल डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोजीशन ऑफ कंट्रीज,” वेलवर्टशाफ्टीज आरची।

आईचेनग्रीन बैरी एंड हुई टांग (2005), ‘इज चाइनाज एफडीआई कर्मिंग एट दि. एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज? एनबीईआर वर्किंग पेपर सं. 11335, मई।

फोरटेनियर,फेबिने (2001), फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओईसीडी, नवंबर।

फुंग, के सी, हितोमिलीजका, सारह टांग (2002), फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना: पॉलिसी, ट्रेड एंड इम्पेक्ट, आईएमएफ वर्किंग पेपर सं.74।

होस्ट.टी.(1972), दि इंडस्ट्रियल कंपोजीशन ऑफ यू.एस. एक्सपोर्ट्स एंड सब्सिडियरी सेल्स टू दि कैनेडियन मार्केट, अमरीकन इकोनॉमिक रिव्यू 62।

हाइमर, स्टीफेन्स एच. (1970), दि इंटरनेशनल आपरेशंस ऑफ नेशनल फर्म्स : ए स्टडी ऑफ डाइरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पीएचडी, थीसिस, कैम्ब्रिज : एमआईटी प्रेस, 1976 में प्रकाशित।

जेंसकिंस, कारोलिन एंड लिने थॉमस (2002), फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सदर्न अफ्रीका : डिटरमिनेंट्स, करेक्टरीस्टिक्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पावर्टी एलिवियेशन, अक्टूबर।

कीर्ने ए.टी. 2010, “ए टी कीर्ने ग्लोबल मैनेजमेंट कंसलटेंट्स : एक्सपांडिंग अपार्चुनिटीज फॉर ग्लोबल रिटेलर्स, दि 2010 ए.टी कीर्ने ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स।

लिप्से, राबर्ट ई (2007) ‘डिफाइनिंग एंड मीजरिंग दि लोकेशन ऑफ एफडीआई’, आउटपुट एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.12996, मार्च,

लांग, गुओक्वियांग (2005), ‘चाइनाज पॉलिसीज ऑन एफडीआई: रिव्यू एंड इवेल्युएशन’ इन डज फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोमोट डेवलपमेंट? संपादित, मॉरान थियोडोर एच, एडवार्ड एम. ग्राहम एंड मैगनस ब्लॉमस्ट्रॉम, इस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स।

मैगनस ब्लॉमस्ट्रॉम (2001), फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्पिलओवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट।

ऑक्सेलहीम, एल. (1983), “फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड दि लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स” इन आक्सेलहीम, एल (संपा.), दि ग्लोबल रेस फॉर फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट - प्रोस्पेक्ट्स फॉर दि फ्यूचर, बर्लिन, और न्यूयार्क : स्पिंगर वर्लाग।

पितेली इलेनी, ई.एन (2010), डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपड कंट्रीज: ए कंपेरिजन बिटवीन यूरोपियन एंड

नॉन यूरोपियन कंट्रीज, *कंट्रीब्यूशंस टु पॉलिटिकल इकोनॉमी* खंड 29, पीपी 111-128।

राजन, रामकिशन, एस सुनील रांगाला और राम्या घोष (2008), 'अट्रेक्टिंग फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई)टु इंडिया' अप्रैल।

रेजिन, आसफ और इफ्रेम सादका (2007), प्रोडक्टिविटी एंड टैक्सेज एन ट्राइवर्स ऑफ एफडीआई, 'एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.13094, मई।

रेजिन, आसफ, योना रूविन्सटीन ईफ्रेमसादका (2004), फिक्सड कॉस्ट्स एंड एफडीआई : दि कंफ्लिक्टिंग इफेक्ट्स आफ प्रोडक्टिविटी शॉक्स, 'एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.10864, अक्टूबर।

रूगमैन, ए.एम (1980), "इंटरनेशनलाइजेशन एज ए जनरल थियोरी ऑफ फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ए रिएप्रेजल ऑफ दि लिटरेचर" *वैल्टवर्स्ट्सचैफीलिचेस आर्चिव*।

शाह, अजय एंड इला पटनायक (2007), इंडियाज इक्सपेरीएंस विथ कैपिटल फ्लोज: दि इलूसिव क्वेस्ट फॉर ए सस्टेनेबल करेंट

एकाउंट डिफिसिट इन सेबेस्टियन इडवर्ड्स (संपा) 'कैपिटल कंट्रोल्स एंड कैपिटल फ्लोज इन इमर्जिंग इकोनॉमीज : पॉलिसीज, प्रैक्टिसेज एंड कंसीक्वेंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

टे वेल्डे, डर्क विलेम (2002), 'गवर्नमेंट पालिसीज टुवार्ड्स इनवार्ड फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज: इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इनकम इनेक्वेलिटी,' ओईसीडी *डेवलपमेंट सेंटर वर्किंग पेपर सं.193, अगस्त।*

वाल्श. जेम्स पी, एंड जियानग्यान यू (2010) डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट: ए सेक्टरल एंड इंस्टीट्यूशनल एप्रॉच, *आईएमएफ वर्किंग पेपर सं.187।*

वर्ल्ड बैंक (2010), इन्वेस्टिंग एक्रास वॉर्ड्स - ए सर्वे ऑफ 87 इकोनॉमीज।

व्हीलर डी एंड मोदी, ए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लोकेशन डिजीजन्स : दि केस ऑफ यू.एस फर्म्स, जॉर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, खंड 33, सं.1-2 अगस्त 1992।

विश्व बैंक (2010) 'डूइंग बिजनेस' वैरियस इसूज।